सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

गूगल, पूरी दुनिया का रास्ता दिखा सकता है
पर मनुष्य बनने का रास्ता सिर्फ
धर्म, शिक्षा और संस्कार ही दिखा सकता है..!!

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–52 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 13 मार्च 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए,

महीने भर के क्रिकेट मैच में हजारों रुपए की अर्थव्यवस्था! खेल ने दिखाया असली इकोनॉमिक पावर

टी–20 वर्ल्ड कप देखने 22 लाख दर्शक पहुँचे, टिकट बिक्री से ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई

विशेष संवाददाता संदीप सिंह / नईदिल्ली

दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसकों की धड़कन बने आईसीसी मेन्स टी–20 वर्ल्ड कप 2026 ने जहां मैदान पर रोमांच और जश्न का माहौल बनाया, वहीं पर्दे के पीछे यह टूर्नामेंट हजारों करोड़ की आर्थिक गतिविधि का भी गवाह बना। भारत की जीत के साथ खत्म हुए इस विश्व कप ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक विशाल आर्थिक उद्योग है।

करीब 30 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट के दौरान लगभग 22 लाख दर्शक स्टेडियमों में पहुँचे, जिससे टिकट बिक्री से ही 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई दर्ज की गई। मैचों की मेजबानी करने वाले शहरों में होटल उद्योग की भी चांदी रही। अनुमान के मुताबिक 8 से 10 लाख होटल रूम–नाइट्स बुक हुए, जिससे पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को जबरदस्त फायदा मिला। एयरलाइंस कंपनियों के लिए भी यह टूर्नामेंट बड़ा अवसर साबित हुआ। क्रिकेट प्रेमियों की आवाजाही के चलते करीब 3 से 4 लाख अतिरिक्त फ्लाइट टिकटों की बिक्री हुई। इसके साथ ही शहरों में टैक्सी, लोकल ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट व्यवसाय में भी बड़ी उछाल देखी गई।

क्रिकेट के दीवानों ने टीम और खिलाड़ियों के प्रति अपने जुनून को मर्चेंडाइज के जरिए भी खूलकर दिखाया। अनुमान है कि अगर सिर्फ 15 प्रतिशत प्रशंसकों ने जर्सी खरीदी, तो करीब 30 लाख जर्सियां बाजार में बिकीं। जर्सी के अलावा कैप, झंडे, फेस पेंट और स्मृति–चिह्नों को मिलाकर फैन मर्चेंडाइज का कारोबार 300 से 400 करोड़ रुपये तक पहुँच गया।

मीडिया और विज्ञापन जगत में भी यह टूर्नामेंट सोने की खान साबित हुआ। बड़े मुकाबलों के दौरान 10 सेकंड का विज्ञापन स्लॉट 25 से 30 लाख रुपये तक में बेचा गया। विज्ञापन, ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप को मिलाकर इस विश्व कप की कुल मीडिया वैल्यू 7000 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है।

लेकिन इस आर्थिक लहर के असली नायक वे लोग भी रहे जो सुर्खियों में नहीं आए— स्टेडियम के बाहर सीटी और झंडे बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर, देर रात तक यात्रियों को ढोने वाले टैक्सी ड्राइवर, प्रशंसकों से भरे रेस्टोरेंट के कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, इवेंट मैनेजर और ग्राउंड स्टाफ। सिर्फ एक टूर्नामेंट ने हजारों लोगों की रोजी–रोटी को नई रफ्तार दी।

विशेषज्ञों का मानना है कि एक क्रिकेट मैच भले ही 240 मिनट चलता हो, लेकिन उसका आर्थिक प्रभाव महीनों तक बना रहता है। खेल अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पर्यटन, व्यापार, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग का मजबूत माध्यम बन चुका है।

दरअसल, जहां करोड़ों लोगों का ध्यान जाता है, वहां कारोबार अपने आप पहुंच जाता है। यही कारण है कि आज एक स्टेडियम सिर्फ स्टेडियम नहीं रह गया, बल्कि फ्लडलाइट्स के नीचे खड़ा हजारों करोड़ रुपये का चलता–फिरता बाजार बन चुका है और इस बार के टी–20 विश्व कप ने यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर साबित कर दी।

महादेव मामले में दो आरोपियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

देश के चर्चित महादेव ऑनलाइन बैटिंग कैसे में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कानूनी कारवाई करते हुए दो आरोपियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग कर दी है। करोड़ों के इस सट्टेबाजी नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए ईडी ने रायपुर की विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में याचिका दायर की है। ईडी ने अदालत से शुभम सोनी और अनिल कुमार अग्रवाल उर्फ अतुल अग्रवाल को भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की मांग की है। साथ ही एजेंसी ने भारत और विदेशों में मौजूद उनकी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति भी मांगी है।

6 हजार करोड़ के सट्टेबाजी नेटवर्क पर शिकंजा : ईडी के मुताबिक लगभग 6,000 करोड़ रुपये के अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क की जांच के दौरान सामने आया कि दोनों आरोपी देश छोड़कर फरार हो चुके हैं और फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में छिपे होने की आशंका है। एजेंसी ने बताया कि कई बार समन, लुकआउट सर्कुलर और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद दोनों आरोपियों ने जांच में शामिल होने से परहेज किया।

पहले से फरार है नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड : इसी विशेष अदालत में ईडी की एक और याचिका पर भी सुनवाई चल रही है, जिसमें महादेव ऑनलाइन बुक के कथित प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को भी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की गई है। उस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

हवाला, फर्जी खाते और क्रिप्टो के जरिए खेला गया करोड़ों का खेल : जांच एजेंसियों के अनुसार महादेव सट्टेबाजी नेटवर्क कई ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल और फ्रेंचाइजी के जरिए संचालित होता था। अवैध कमाई को छिपाने के लिए सैकड़ों फर्जी बैंक खाते, कई स्तरों के लेनदेन, हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। बाद में इस रकम को शेल कंपनियों, रियल एस्टेट, शेयर बाजार और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया गया। ईडी का आरोप है कि शुभम सोनी नेटवर्क के प्रमुख प्रमोटरों में से एक थे, जो प्लेटफॉर्म के संचालन और वित्तीय लेनदेन से जुड़े फैसलों में शामिल थे। वहीं अनिल कुमार अग्रवाल तकनीकी संचालन संभालता था, जिसमें सट्टेबाजी वेबसाइटों का विकास, प्लेटफॉर्म इंटरफेस की निगरानी और हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करना शामिल था।

कई राज्यों की जांच के बाद बना बड़ा केस : इस मामले में कार्रवाई की शुरुआत सीबीआई द्वारा जनवरी 2025 में दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई। इससे पहले छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा और महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में दर्ज करीब 77 एफआईआर को मिलाकर यह बड़ा केस बनाया गया था।

अदालत दे सकती है अंतिम चेतावनी : ईडी ने अदालत से अनुरोध किया है कि दोनों आरोपियों को कम से कम छह सप्ताह के भीतर अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया जाए। अगर वे निर्धारित समय में पेश नहीं होते, तो उन्हें औपचारिक रूप से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है। इसके बाद उनकी देश–विदेश में मौजूद संपत्तियों की कुर्की और जब्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। महादेव सट्टेबाजी कांड में ईडी की यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि एजेंसियां अब इस अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी नेटवर्क के आर्थिक साम्राज्य को जड़ से खत्म करने की तैयारी में हैं।

भिलाई निगम में बड़ा सियासी विस्फोट

महापौर नीरज पाल और कांग्रेस पार्षदों का आयुक्त के खिलाफ मोर्चा, कलेक्टर से हटाने की मांग

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

महापौर नीरज पाल के नेतृत्व में नगर पालिक निगम भिलाई की राजनीति में बड़ा सियासी विस्फोट हो गया है। संजय नगर मैदान और अन्य जमीनों की नीलामी को लेकर उठे विवाद के बाद अब महापौर और कांग्रेस पार्षदों ने सीधे निगम आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को महापौर नीरज पाल समेत कांग्रेस के कई पार्षदों ने एकजुट होकर कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को शिकायत भेजते हुए आयुक्त के खिलाफ कड़ी कारवाई और पद से हटाने की मांग कर दी है। इस मामले में मुख्य सचिव को संबोधित पत्र भी सौंपा गया है।

दशहरा मैदान को बेचने की अफवाह पर भी सफाई

महापौर ने कहा कि शांति नगर दशहरा मैदान को बेचने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नगर निगम अधिनियम के अनुसार निगम किसी भी जमीन को बेच ही नहीं सकता। मैदान के संरक्षण और देखरेख के लिए सिर्फ रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) के माध्यम से संस्थाओं की भागीदारी पर विचार किया गया था, जिसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है।

कमिशनखोरी और गड़बड़ी के आरोप

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि निगम में ठेकेदारों के भुगतान को लेकर भी अनियमितताएं हो रही हैं। आरोप है कि जो ठेकेदार कमीशन देते हैं उन्हें भुगतान में प्राथमिकता मिलती है, जबकि अन्य ठेकेदार लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

एक हफ्ते में कार्रवाई नहीं तो आंदोलन

महापौर और पार्षदों ने राज्य शासन से मांग की है कि एक सप्ताह के भीतर आयुक्त के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाए, अन्यथा निगम के पार्षद आंदोलन और न्यायालय की शरण लेने को मजबूर होंगे।

कांग्रेस पार्षदों ने खोला मोर्चा

इस शिकायत पत्र में कई पार्षदों ने हस्ताक्षर कर आयुक्त के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। इनमें प्रमुख रूप से संदीप निरंकारी, अभय सोनी, निगम सभापति गिरवर बंटी साहू, एकांश बंछोर, हरिओम तिवारी, रविशंकर कुर्रे, राजेश चौधरी, भूपेंद्र यादव, जगदीश, चंद्रशेखर गवई, नेहा साहू, आदित्य सिंह, ऊषा शर्मा, सीजू एंथोनी, मन्नान गफ्फार खान, लक्ष्मीपति राजू, सेवन ठाकुर, अभिषेक मिश्रा और शुभम झा शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री को भी भेजी प्रतिलिपि

महापौर नीरज पाल ने बताया कि शिकायत की प्रतिलिपि राज्य के उपमुख्यमंत्री अरुण साव तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को भी भेजी गई है। अब इस पूरे मामले ने भिलाई की राजनीति को गरमा दिया है और आने वाले दिनों में निगम की सियासत में बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है।

4.50 करोड़ और 21.54 करोड़ के कामों पर भी सवाल

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि डीएमएफ मद से 4.50 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति, वार्ड क्रमांक 4 में 21 करोड़ 54 लाख रुपये के विकास कार्य, बिना एमआईसी और सामान्य सभा की मंजूरी के ही स्वीकृत कर दिए गए, जो पूरी तरह नियम विरुद्ध हैं। इन कार्यों की निविदा खोलने की तिथि 12 मार्च 2026 बताई गई है।

बिना शासन अनुमति निकाली नीलामी - महापौर का आरोप

महापौर नीरज पाल ने आरोप लगाया कि सत्र 2021–22 में निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से परिषद ने निगम की व्यावसायिक जमीनों को 30 वर्ष की लीज पर देने का प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा था। लेकिन शासन से अब तक अनुमति नहीं मिलने के बावजूद आयुक्त ने संजय नगर मैदान समेत अन्य जमीनों की नीलामी के लिए ई–टेंडर पोर्टल पर निविदा अपलोड कर दी, जो नियमों के खिलाफ है और एमआईसी तथा सामान्य सभा के अधिकारों का अतिक्रमण है।

सीजी पीएससी अधीक्षक परीक्षा देवांगन समाज के 3 अभ्यर्थी चयनित : नगपुरा के रोहित मेरिट में 5वें स्थान पर रहे

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) पद हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी पीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा 2025 के 11 मार्च को घोषित चयन सूची में नगपुरा के रोहित कुमार देवांगन ने मेरिट में गौरवशाली पांचवां स्थान प्राप्त किया है। सीजी पीएससी द्वारा कुल 47 विज्ञापित पदों के लिए घोषित अंतिम चयन सूची में रोहित देवांगन के अलावा प्रवीण कुमार मेहर 34 वें एवं आयुषी देवांगन 42 वें रैंक पर चयनित हुए हैं। अनुपम देवांगन 66 वें स्थान पर हैं किन्तु प्रतीक्षा सूची पर हैं।

रोहित देवांगन, प्रवीण कुमार मेहर एवं आयुषी देवांगन की गौरवशाली उपलब्धि पर देवांगन समाज के वरिष्ठ सलाहकार घनश्याम कुमार देवांगन ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इससे समग्र देवांगन समाज गौरवान्वित हुआ है। ये समाज के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। देवांगन समाज के इन तीनों विशिष्ट प्रतिभाओं को समाज के आगामी समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) पद मेरिट में पांचवें स्थान पर चयनित रोहित देवांगन ने बताया कि वर्ष 2025 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद साक्षात्कार में 138 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें उन्हें मेरिट में पांचवां स्थान मिला। उन्होंने बताया कि विगत 10 वर्षों से विभिन्न पदों के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं, पर कुछ अंकों से पीछे रह जाते थे। पर हिम्मत न हारकर दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास के बलबूते अंततः सफलता मिली।

उन्होंने बताया कि वे पांच बार मेन्स परीक्षा उत्तीर्ण किए किंतु साक्षात्कार में फेल होते रहे। वे एक बार 2019 में कोचिंग किए थे, किंतु बाद में स्वतः की तैयारी एवं मेहनत से सफल हुए। वे नगपुरा निवासी कृषक भगवती देवांगन के छोटे सुपुत्र हैं। उनके पिता का गांव में ही किराना दुकान भी है। मां ढेलाबाई गृहणी हैं। रोहित के दो बड़े भाई और दो बड़ी बहनें हैं, जो विवाहित हैं। रोहित अपनी सफलता का श्रेय अपने माता–पिता एवं सभी भाई भाभियों को देते हैं, जिन्होंने उसे लगातार असफल होने के बाद भी स्पोर्ट किया। रोहित की सफलता से नगपुरा वासी एवं समग्र देवांगन समाज में हर्ष व्याप्त है।

झुग्गी–झोपड़ी प्रकोष्ठ की जिला टीम घोषित, मनोज को फिर मिली कमान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय से जारी आदेश में झुग्गी–झोपड़ी प्रकोष्ठ की जिला इकाई के संयोजक और सहसंयोजकों की घोषणा कर दी गई है। यह नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से की गई हैं।

जारी सूची के अनुसार भिलाई जिले में मनोज तिवारी को एक बार फिर जिला संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि मनोज तिवारी पूर्व में भी इसी दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके अनुभव और संगठनात्मक सक्रियता को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने दोबारा उन पर भरोसा जताया है।

वहीं सहसंयोजक के रूप में प्रेमाचंद गिरी, रामानुज प्रसाद और हेमंत बेहरा को जिम्मेदारी दी गई है। नई टीम के गठन के साथ संगठन ने झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने और वहां रहने वाले लोगों की समस्याओं को संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है।

इसी के साथ महिला मोर्चा में भी संगठन ने निरंतरता बनाए रखते हुए स्वीटी कौशिक को दोबारा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि अन्य पदों पर नए पदाधिकारियों को अवसर दिया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नई टीम के गठन के बाद जल्द ही बस्तियों में संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। नई नियुक्तियों पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।

पूरी निष्ठा से निभाऊंगा संगठन की जिम्मेदारी

नवनियुक्त संयोजक मनोज तिवारी ने कहा कि मुझे झुग्गी–झोपड़ी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बनाकर दोबारा यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। यह मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पद का निर्वहन सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हुए संगठन को मजबूत बनाने तथा झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दुर्ग लोकसभा के माननीय सांसद एवं वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है।

पार्टी का जताया आभार

झुग्गी–झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ठाकुर भानूप्रताप सिंग ने भाजपा संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मान और विश्वास के लिए मैं विशेष रूप से प्रदेश नेतृत्व, दुर्ग के सांसद, झुग्गी–झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक तथा सांसद प्रतिनिधि का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने मुझ पर जो विश्वास और भरोसा जताया है, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। पार्टी की विचारधारा और संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की सेवा ही मेरा संकल्प है।

महत्वपूर्ण सूचना! हमारे पाठकों के लिए

सांध्य दैनिक नई दृष्टिबिंदु

सांध्य दैनिक नई दृष्टिबिंदु का E-Paper भी तैयार है। प्रतिदिन शाम 4:00 बजे पेपर नई दृष्टिबिंदु के गूगल के साइट Nayi Drishtibindu पर अपलोड हो जाता है। सभी पाठकों से आग्रह है कि प्रतिदिन शाम 4:00 बजे साइट पर Nayi Drishti bindu E-Paper सर्च कर ई पेपर देख सकते हैं।

Google
NAYI DRISHTIBINDU E-PAPER

शाम 4 बजे से पढ़े

न्यायिक कर्मियों के लिए आवासों का लोकार्पण किया छग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने उच्च न्यायालय न्यायिक कर्मचारी आवासीय परिसर, सेक्टर-3, रहंगी रोड बिलासपुर में कर्मचारियों के लिए नव-निर्मित एच एवं आई - टाइप आवासीय मकानों का लोकार्पण किया। उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायिक कर्मचारियों के लिए बोदरी, बिलासपुर में नवीन निर्मित एच - टाईप के 32 एवं आई - टाईप के 80 की कुल 112 आवासगृहों का लोकार्पण न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने किया। उन्होंने आबंटित आवास की चाबी संबंधित कर्मचारियों को प्रदान की।

इस अवसर पर न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार व्यास, न्यायाधीश नरेश कुमार चन्द्रवंशी, न्यायाधीश सचिन सिंह राजपूत, न्यायाधीश राकेश मोहन पाण्डेय, न्यायाधीश राधाकिशन अग्रवाल, न्यायाधीश संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश विभू दत्ता गुरु एवं न्यायाधीश अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति रही।

मुख्य न्यायाधीश ने अपने सम्बोधन में कहा कि यह आवास कर्मचारियों की लगन और परिश्रम का परिणाम है। यदि व्यक्ति निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करता है, तो उसे अवश्य ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि सभी कर्मचारी अपने माता-पिता का सम्मान करते हुए अपने परिवार के साथ इन आवासों में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली के साथ जीवन यापन करेंगे।

यह उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधिपति द्वारा पद भार ग्रहण करने के पश्चात सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के दूरस्थ जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालयों का भ्रमण कर न्यायिक अधोसंरचना एवं आवश्यक सुविधाओं का अभाव डोने से पक्षकारों, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी एवं अधिकारियों को होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये दूरदर्शितापूर्ण एवं सकारात्मक सोच के भागीरथ प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में न्यायिक अधोसंरचना से अभूतपूर्व विकास का कार्य हो रहा है। इसी क्रम में उच्च न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय आवासीय परिसर, सेक्टर-3, रडंगी रोड, बोदरी, बिलासपुर में नवीन निर्मित एच टाईप के 32 एवं आई - टाईप के 80, कुल 112 आवासगृहों का लोकार्पण किया गया। आवासगृह में भू-तल पर पार्किंग की सुविधा के साथ-साथ बेडरूम, किचन, मल्टीपरपस रूम, यूटिलिटी एवं प्रसाधन कक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा, सभी भवनों में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में छ.ग. उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं रजिस्ट्री के अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ न्यायिक एकेडमी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीगण, न्यायालयीन कर्मचारी और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि शामिल थे।

खास खबर

गर्भवती माताओं को दी पौष्टिक आहार की जानकारी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शैलदेवी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने गुण्डरदेही के ग्राम गोंडेला आंगनबाड़ी केंद्र में सुपोषण चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों को जागरूक किया। इस दौरान गर्भवती माताओं और अन्य ग्रामीणों को एकत्रित कर पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने बताया कि रेडी टू ईट पाउडर, हरी सब्जियां, मूंग, चना और विभिन्न प्रकार की भाजी को नियमित आहार में शामिल करने से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

कार्यक्रम में सरपंच वागीश बंजारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ सचिव लीलाधर साहू, पंच राजेश साहू और सहायक प्राध्यापक ढाल सिंह साहू भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज कार्य के विद्यार्थियों लेमन, विनय, दामन, विकास, आरती, डोमेश्वरी, नम्रता, ललिता, लोकेश्वरी, संजय, चंद्रशेखर, पदमनी, सिमरन, हेमिन, सरिता, ज्योति, यशोनिधि, पामेश्वरी, मनीषा, रामेश्वर, देविका और टिकेश्वरी का विशेष योगदान रहा।

नगर निगम भिलाई का नागरिकों को संदेश-जल संरक्षण जरूरत भी, कर्तव्य भी

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में बढ़ती गर्मी एवं तापमान में लगातार वृद्धि के कारण जल स्त्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। जिससे जल संरक्षण की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार सभी जोन क्षेत्रों में जल संरक्षण को लेकर एक अहम कदम उठाते हुए सभी सार्वजनिक खुले नलों में टोटी लगाने का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी का अनावश्यक उपयोग न करें और जल संरक्षण के उपयों को अपनाये। घरो में पानी का सीमित उपयोग, वर्षा जल संचयन प्रणाली का उपयोग तथा नलों को खुला न छोड़ने जैसी छोटी-छोटी सावधानियां बड़े स्तर पर पानी की बचत कर सकती है। आयुक्त के आदेशानुसार गर्मी के मौसम में जलापूर्ति बनाए रखने के लिए टंकियों की नियमित सफाई, पाईप लाईन लीकेज की मरम्मत और जल वितरण व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। साथ ही संरक्षण को लेकर शहर में डोर-टू-डोर पाम्पलेट वितरण भी किया जा रहा है। हम सब अभी से पानी के संरक्षण पर ध्यान नहीं देगें तो आने वाले समय में जल संकट और गंभीर हो सकता है।

घरेलू गैस व डीजल-पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता घबराने की जरूरत नहीं- कलेक्टर अभिजीत

शिकायत या जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-3555 पर करें संपर्क

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिले में घरेलू एलपीजी गैस तथा डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ऑयल कंपनियों के अधिकारियों, डिस्ट्रीब्यूटरों और गैस एजेंसियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने घरेलू गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली।

बैठक में ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और इसकी आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि जिले के सभी एलपीजी वितरक के पास गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

कलेक्टर ने बताया कि उज्ज्वला योजना के कनेक्शन को मिलाकर जिले में लगभग 4 लाख गैस कनेक्शन हैं। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 9750 गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही है। कलेक्टर ने अधिकारियों को एलपीजी गैस की दैनिक आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी न होने दी जाए।

ऑयल कंपनी के अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि वर्तमान में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर केवल विशेष अत्यावश्यक संस्थानों जैसे अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को ही सप्लाई किए जा रहे हैं। बैठक में जिले में डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में डीजल-पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और इसकी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि जिन उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी नहीं हुआ है, वे संबंधित गैस एजेंसी में जाकर जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लें, ताकि भविष्य में परेशानी न हो। इस प्रक्रिया में फेस स्कैन और अंगूठे का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें केवल एक मिनट का समय लगता है। जिला प्रशासन एवं ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि घबराने या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिले में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। त्यौहार के बाद बुकिंग की संख्या बढ़ने के कारण कुछ स्थानों पर प्रतीक्षा हो सकती है, लेकिन आपूर्ति नियमित रूप से जारी है।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिले में एलपीजी गैस तथा डीजल-पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। गैस सिलेंडरों की आपूर्ति गैस एजेंसियों के माध्यम से नियमानुसार नियमित रूप से की जा रही है। उन्होंने बताया कि आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3555 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया एवं आयल कंपनी के अधिकारी सहित खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

गैस सिलेंडर की किल्लत केवल अफवाह, अनावश्यक भंडारण न करें - विधायक रिकेश सेन

बातचीत

कलेक्टर दुर्ग से चर्चा के बाद विधायक ने की जन अपील, कहा- पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है स्टॉक

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति या हड़बड़ी में न आएं। विधायक ने स्पष्ट किया है कि जिले में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।

कलेक्टर से चर्चा और स्थिति की समीक्षा

जनता के बीच सिलेंडर की किल्लत को लेकर फैल रही चर्चाओं को गंभीरता से लेते हुए विधायक रिकेश सेन ने कलेक्टर दुर्ग से विस्तृत चर्चा की। चर्चा के उपरांत विधायक ने आश्वस्त किया कि प्रशासन और गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अफवाहों के चलते घबराने की आवश्यकता नहीं है।

अनावश्यक भंडारण से बचने की सलाह

विधायक श्री सेन ने नागरिकों से विशेष आग्रह किया है कि वे "सिलेंडर नहीं मिलेगा" जैसी अफवाहों के आधार पर अनावश्यक रूप से अतिरिक्त सिलेंडरों का भंडारण न करें। बेवजह भंडारण करने से कृत्रिम किल्लत पैदा होती है, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

विधायक ने क्षेत्रवासियों को मौजूदा नियमों के तहत धैर्य बनाए रखने को कहा है। नियमानुसार एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगले सिलेंडर की बुकिंग के लिए निर्धारित समय अंतराल का पालन करना अनिवार्य है। सभी उपभोक्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बुकिंग और डिलीवरी की सूचना प्राप्त हो रही है। एजेंसियां क्रमानुसार सिलेंडर की आपूर्ति कर रही हैं।

श्री सेन ने वैशाली नगर की जनता से अपील है कि आप संयम बरतें। शासन और प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर घर तक रसोई गैस पहुंचे और किल्लत जैसी कोई बात है ही नहीं, हमेशा की तरह मांग अनुरूप आपूर्ति का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। विधायक ने अंत में दोहराया कि साय सरकार सुशासन के संकल्प के साथ काम कर रही है और जनसुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

महापौर अल्का बाघमार की अपील: शादियों में नव-दंपतियों को भेंट करें हेलमेट

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शहर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने एक अनोखी पहल करते हुए तीन अलग-अलग शादियों में पहुंचकर नव-विवाहित वर-वधु को शुभकामनाएं दीं और उन्हें हेलमेट भेंट किया। इस अवसर पर एमआईसी शशि साहू, सरिता चंद्रकार, सुरुचि उमरे सहित अन्य मौजूद रही।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने नव-दंपतियों को उनके नए जीवन की मंगलकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन अनमोल है और इसकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उन्होंने नव-दंपतियों से अपील की कि वे स्वयं भी हेलमेट पहनें और अपने परिवार व समाज को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम किया जा सके। महापौर की इस पहल को उपस्थित लोगों ने सराहा और इसे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने वाला सराहनीय कदम बताया।

महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि शादियों में केवल फूल-गुलदस्ते देने की परंपरा के बजाय नवदंपतियों को हेलमेट भेंट करने की पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हेलमेट एक जीवन कवचद्ध है, जो सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि यदि शादी जैसे शुभ अवसरों पर हेलमेट भेंट करने की परंपरा शुरू हो जाए तो इससे समाज में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को सुरक्षित जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से इस सराहनीय पहल को अपनाने की अपील की।

संगठन की गतिविधियों को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने में मीडिया आईटी सेल व सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण-परिहार

नई दृष्टिबिंदु / ooooo

भाजपा आईटी सेल एवं सोशल मीडिया विभाग की संयुक्त बैठक भारतीय जनता पार्टी के मीडिया, आईटी सेल एवं सोशल मीडिया विभाग की संयुक्त बैठक जिला भाजपा कार्यालय दुर्ग में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला भाजपा उपाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह परिहार ने की। इस दौरान जिला महामंत्री एवं जिला प्रशिक्षण वर्ग के प्रमुख दिलीप साहू, महामंत्री विनोद अरोरा, प्रशिक्षण वर्ग टोली सदस्य राजेंद्र पाण्डे, जिला मीडिया प्रभारी राजा महोबिया, सोशल मीडिया संयोजक रजनीश श्रीवास्तव तथा आईटी सेल संयोजक जितेंद्र सिंह राजपूत सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में मंडल स्तर एवं विभिन्न मोर्चे के जिला स्तर के मीडिया, आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी शामिल हुए। इस दौरान आगामी दिनों में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण वर्ग तथा संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और पदाधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

अध्यक्षता करते हुए शिवेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव चरैवेति-चरैवेति के मूल मंत्र पर कार्य करती है और संगठनात्मक गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी नवाचार को प्राथमिकता देती है और संगठन की गतिविधियों को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने में मीडिया, आईटी सेल और सोशल मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

जिला महामंत्री एवं प्रशिक्षण वर्ग के प्रमुख दिलीप साहू ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित पार्टी है और सर्वप्रथम राष्ट्र, द्वितीय संगठन और अंत में हम के सिद्धांत पर कार्य करती है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित, समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं के बल पर ही मजबूत संगठन का निर्माण संभव है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण वर्ग में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण वर्ग टोली सदस्य राजेंद्र पाण्डे ने अपने संबोधन में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पार्टी की रचनात्मक गतिविधियों और प्रामाणिक जानकारी को जनता तक पहुंचाना जरूरी है तथा भ्रामक सूचनाओं से दूर रहना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग के दौरान प्रेस विज्ञप्ति, फोटो अपलोड, आईटी सेल के माध्यम से पंजीयन और पावर प्रेजेंटेशन जैसे कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने पर भी जोर दिया।

बैठक को जिला मीडिया प्रभारी राजा महोबिया, सोशल मीडिया प्रभारी रजनीश श्रीवास्तव और आईटी सेल प्रभारी जितेंद्र सिंह राजपूत ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम का संचालन आईटी सेल जिला सहसंयोजक उमेश गिरी ने किया, जबकि आभार सोशल मीडिया सहसंयोजक अविनाश राजपूत ने व्यक्त किया।

बैठक में जिला भाजपा सह मीडिया प्रभारी संजय सेंगर, आईटी सेल जिला सहसंयोजक जूही चंद्राकर, सविता साहू, श्वेता बक्शी, सरला चौहान, इंदु साहू, इंदुबाला गोस्वामी, सोनिया मिश्रा, विजय कांत बंछोर, होमेंद्र साहू, जितेंद्र सोनी, अश्वनी यादव, ईश्वर कुमार, विवेक कुमार, पन्ना, आंचल यादव, अरुण सिंह राजपूत, दयानंद सिन्हा, रविकांत ठाकुर, संतोष चौधरी, यश सिंह बैस, चमन यादव, पुष्कर साहू, मुकुंद विश्वकर्मा, प्रवीण वर्मा, लुभम बंछोर, महेश साहू, हर्ष साहू, अभिषेक सेन, हुमन लाल देशमुख, मंगेश बोकारे, धनंजय ठाकुर, अमित कुमार अग्रे, संजय कुमार नामदेव, शुभम सोनवानी, डी. गणपति, डी. बालाजी, केवल देवांगन, वेद प्रकाश वर्मा, राहुल देव यादव, राकेश देवांगन, सुरेश निषाद, नीलकमल साहू, कुलेश्वर प्रसाद साहू, दिनेश कुमार राजपूत, लोकेश्वर साहू, गौतम साहू, वेद निरंकारी, दीपक सिंह ठाकुर, अवधेश दुबे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने जनदर्शन कार्यक्रम में सुनी लोगों की समस्याएं

राजीव नगर वार्ड क्रमांक 29 के वार्डवासियों ने बेदखली से पूर्व प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की मांग की

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर हितेश पिस्दा भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित 136 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्राप्त अनेक आवेदनों पर त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर प्रकरणों की जानकारी ली और तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इसी कड़ी में संयोजक हुडको संघर्ष समिति ने पेयजल पाइपलाइन में लीकेज को सुधारने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 69,70 (हुडको) में पेयजल आपूर्ति की एमडीपी पाइपलाइन में लगातार लीकेज की समस्या आ रही है। वर्ष 2014-15 में बिछाई गई एमडीपी पाइपलाइन से 2021 में पानी की आपूर्ति शुरू हुई, लेकिन लंबे समय तक खाली रहने के कारण पाइप की गुणवत्ता कमजोर हो गई है, जिससे करीब दो दर्जन जगहों पर पाइप फटने की शिकायतें मिली है। समिति ने स्थायी समाधान के लिए एमडीपी की जगह डीआई पाइप लगाने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त भिलाई को निरीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

दीक्षित कालोनीवासियों ने कोसानगर भिलाई में किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। कालोनीवासियों ने बताया कि 15 फीट की कच्ची सड़क पर टीन शेड लगाकर कब्जा कर लिया गया है और आगे जाने वाले मार्ग पर लोहे का गेट, पानी की टंकी व बोरिंग कर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसके कारण असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई को निरीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

ग्राम नगपुरा के ग्रामवासियों ने रेबीज टीका उपलब्ध कराने आवेदन दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगपुरा सहित जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों में रेबीज (कुत्ता काटने) का टीका उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि टीका नहीं मिलने के कारण पीड़ितों को उपचार के लिए सीधे जिला अस्पताल दुर्ग जाना पड़ता है। उन्होंने नगपुरा सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रेबीज टीका उपलब्ध कराने की मांग की । इस पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

राजीव नगर वार्ड क्रमांक 29 वार्डवासियों ने बेदखली के पूर्व प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने आवेदन दिया। नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा के वार्ड क्रमांक 29 राजीव नगर में रेलवे भूमि पर बसे लगभग 150 परिवारों ने संभावित बेदखली को लेकर चिंता जताई। बस्तीवासियों ने बताया कि वे कई दशकों से यहां रह रहे हैं और वर्ष 2003 से बिजली कनेक्शन सहित नगर निगम की कई बुनियादी सुविधाएं भी मिल रही हैं। रेलवे विभाग द्वारा बेदखली की कार्रवाई की जाती है तो उससे पहले सभी प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास उपलब्ध कराया जाने की मांग की, ताकि गरीब परिवारों को बेघर होने की स्थिति का सामना न करना पड़े।

राजधानी क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास से छत्तीसगढ़ को मिलेगा नया ग्रोथ इंजन : मुख्यमंत्री साय

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (स्टेट कैपिटल रीजन-SCR) की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राधिकरण के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, गतिविधियों तथा राजधानी क्षेत्र के समग्र और योजनाबद्ध विकास की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की परिकल्पना शहर की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार-वाणिज्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की पहली बैठक अत्यंत सार्थक रही

है और विभिन्न विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा के सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजधानी रायपुर और आसपास के शहर तेजी से विकसित होते हुए एक बड़े शहरी क्षेत्र का रूप ले रहे हैं, इसलिए महानगरों की तर्ज पर इनके संतुलित और योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा से जनता की अपेक्षाएँ भी बढ़ी हैं और इन अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित योजना और समयसीमा के अनुरूप पूरे किए जाएं तथा प्रगति की नियमित रूप से उच्चस्तरीय समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

बैठक में बताया गया कि राजधानी रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें रायपुर, दुर्ग-भिलाई, नवा रायपुर अटल नगर और आसपास के क्षेत्र शामिल होंगे। यह क्षेत्र बड़े महानगरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और भविष्य में छत्तीसगढ़ के विकास का एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बनेगा।

बैठक में राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स के विकास, मेट्रो संचालन के लिए टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी, सर्वेक्षण कार्यों के संचालन तथा इसके लिए विशेषज्ञ सलाहकारों की नियुक्ति पर विचार किया गया। साथ ही प्राधिकरण के प्रशासकीय और वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन, ऑडिट सेवाओं के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति और प्लानिंग प्रभाग के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में राजधानी क्षेत्र विकास एवं निवेश योजना तैयार करने की कार्ययोजना पर भी विचार किया गया। इसके अंतर्गत निवेश क्षेत्रों का विधिवत चिन्हांकन, आवश्यक सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं अध्ययन तथा चरणबद्ध रूप से परियोजनाओं के क्रियान्वयन की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही राजधानी क्षेत्र में भूमि विकास और आबंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश जारी करने पर सहमति बनी। बैठक में प्राधिकरण की प्रारंभिक गतिविधियों के लिए 27 करोड़ रुपये के प्रावधान की जानकारी भी दी गई।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकित आनंद, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., एनआरडीए के सीईओ चंदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि भौगोलिक दृष्टि से देश के मध्य में स्थित छत्तीसगढ़ व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। स्टेट कैपिटल रीजन के विकास से राजधानी और आसपास के शहरों में योजनाबद्ध शहरी विस्तार, बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी, आधुनिक अधोसंरचना और निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

खास खबर

नेशनल लोक अदालत का आयोजन कल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में 14 मार्च 2026 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह कैलेण्डर वर्ष 2026 की पहली लोक अदालत होगी।

लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आवकारी से संबंधित प्रकरणों के निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।

नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा. 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, यादादाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के

अमृत मित्र महोत्सव में शामिल होने स्वसहायता समूहों की 75 महिलाओं मंत्री साव ने किया रवाना

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर रेल्वे स्टेशन मुख्य प्लेटफार्म नंबर 1 में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरूण साव ने नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे सहित शुक्रवार को भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित अमृत मित्र महोत्सव में सम्मिलित होने छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न नगरीय निकायो की स्वसहायता समूहो की 75 महिलाओ को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उपमुख्यमंत्री अरूण साव एवं महापौर मीनल चौबे ने बुके देकर स्वसहायता समूहो की 75 महिलाओ को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की विशेष बोगी से नई दिल्ली के लिए अमृत मित्र महोत्सव आयोजन में सम्मिलित होने रवाना किया। इस अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप, छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुष्यंत रायस्त सहित छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास

अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील अग्रहरी, नगर पालिक निगम रायपुर के अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय, उपायुक्त अमृत मित्र योजना जसदेव सिंह बाबरा सहित छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं नगर पालिक निगम रायपुर के अन्य संबंधित अधिकारियों, रेल्वे अधिकारियों, रेल्वे पुलिस अधिकारियों की रायपुर रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पर उपस्थिति रही।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरूण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिये यह गौरव का विषय है कि, अमृत मित्र महोत्सव में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों से 75 स्व-सहायता समूहों के महिलाओं द्वारा भाग लिया जा रहा है। इनमें रायपुर नगर पालिक निगम से 15 महिलाएं, बिलासपुर नगर पालिक निगम से 15 महिलाएं, लोरमी नगर पालिका से 15 महिलाएं, मुंगेली नगर पालिका से 15 महिलाएं, रतनपुर नगर पालिका से 7 महिलाएं एवं कोटा नगर पंचायत से 8 महिलाएं भाग लेंगी। आज समस्त महिलाएं नई दिल्ली के लिये रवाना हो रही है। शुक्रवार को कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात महिलाओं को दिल्ली भ्रमण कराया जाना भी प्रस्तावित है। महिलाओं के लिये समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गयी है।

उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बताया कि अमृत मित्र महोत्सव में देश के सभी प्रदेशों से कुल 1000 स्व-सहायता समूह की महिलाएं भाग लेंगी। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरी सेवाओं में सामुदायिक भागीदारी को सशक्त बनाना, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को राष्ट्रीय मंच देना, महिलाओं का सम्मान करना, राज्यों में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का प्रस्तुतिकरण करना है।

उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने समस्त 75 महिलाओ को शुभ यात्रा हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा वूमन फॉर ट्री अमृत मित्र योजना प्रारंभ की गयी है। जिसके अंतर्गत स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया है एवं 1 वर्ष तक रोपित पौधों के संचालन एवं संधारण का कार्य किया जा रहा है, जिस हेतु प्रति माह प्रति महिला को 8 हजार रूपये मानदेय प्रदान किया जा रहा है। वूमन फॉर ट्री योजनांतर्गत कुल 444 परियोजनाएं राशि रु. 27.48 करोड़ की स्वीकृत की गयी है। योजनांतर्गत 1701 महिलाओं द्वारा कुल 1 लाख 61 हजार पौधे रोपित किये गये हैं।

प्रदेश में अवैध धर्मांतरण पर सख्ती : धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 के मसौदे को कैबिनेट की मिली मंजूरी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य से राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 का प्रारूप तैयार किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के अनुसार प्रस्तावित कानून के तहत बल, प्रलोभन, दबाव, मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराना प्रतिबंधित होगा। इसका उद्देश्य धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी और कानूनी बनाना है।

प्रस्तावित प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम प्राधिकारी को पहले से सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन की प्रस्तावित जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान भी रखा गया है।

विधेयक में प्रलोभन, प्रपीड़न, दुर्व्यपदेशन, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। कानून में अवैध धर्मांतरण के मामलों में कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से धर्मांतरण कराता है तो उसे 7 से 10 वर्ष तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है।

वहीं यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो सजा बढ़ाकर 10 से 20 वर्ष तक की जेल और न्यूनतम 10 लाख रुपये जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में और भी कठोर प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित विधेयक के तहत आने वाले अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे तथा इनकी सुनवाई विशेष न्यायालय में की जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं, बल्कि अवैध और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाना है।

विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का बड़ा ऐलान अस्पतालों में की गई अटैचमेंट नियुक्तियों होंगीं रद्द

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का गुरुवार को नौवां दिन रहा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसमें कई विभागों के कामकाज और बजट को लेकर चर्चा हुई। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में की गई अटैचमेंट नियुक्तियों को रद्द किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों से कर्मचारियों को अटैच कर शहरी अस्पतालों में पदस्थ किया गया है, जिससे गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने ऐसे सभी अटैचमेंट को निरस्त करने का निर्णय लिया है, ताकि ग्रामीण

अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध रह सके।

प्रश्नकाल के दौरान मंत्री अपने ही दल की विधायक लता उसेंडी के सवालों से भी घिरते नजर आए। लता उसेंडी ने स्वास्थ्य विभाग में कार्य पूरा होने के बावजूद भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई मामलों में ठेकेदारों ने काम पूरा कर दिया, लेकिन अब तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी कभी मौखिक वर्क ऑर्डर के आधार पर भुगतान कर देते हैं, तो कभी उसी आधार पर भुगतान से इंकार कर देते हैं। विधायक ने यह भी कहा कि नौ महीने पहले अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने भी सरकार को घेरते हुए स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और जवाब की मांग की। सदन में इस विषय को लेकर कुछ समय तक तीखी बहस देखने को मिली।

छत्तीसगढ़ में बनेगा कर्मचारी चयन मंडल, व्यापम होगा भंग

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में कर्मचारी चयन मंडल के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद अब राज्य सिविल सेवा परीक्षा को छोड़कर अधिकांश सरकारी भर्तियां इसी नए मंडल के माध्यम से की जाएंगी।

सरकार के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) को भंग कर दिया जाएगा और उसकी जगह कर्मचारी चयन मंडल काम करेगा। कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के अनुसार नया मंडल व्यापम की तुलना में अधिक सशक्त होगा और भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में काम करेगा।

नया बोर्ड होगा ज्यादा मजबूत

राज्यपाल की अधिसूचना जारी होते ही व्यापम को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान में व्यापम की अध्यक्ष रेणु पिल्हे ही कर्मचारी चयन मंडल की चेयरमैन होंगी। हालांकि नए मंडल में चेयरमैन के साथ-साथ पीएससी की तरह सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी। चेयरमैन और सदस्य सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी होंगे और सभी महत्वपूर्ण फैसले पूर्ण बोर्ड द्वारा लिए जाएंगे।

भर्ती में गड़बड़ियों के बाद लिया फैसला

पिछले समय में शिक्षक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती जैसी प्रक्रियाओं में सामने आई समस्याओं के बाद सरकार ने मजबूत भर्ती तंत्र बनाने का फैसला किया। कई मामलों में भर्ती प्रक्रिया में देरी और चयन में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके कारण हजारों पद खाली रह गए थे।

अब एक साथ होंगी परीक्षाएं

नए कमचारी चयन मंडल का उद्देश्य विभिन्न विभागों की समान प्रकृति की परीक्षाओं को एक साथ आयोजित करना है। इसके लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा और तय समय में परीक्षा और परिणाम घोषित किए जाएंगे। इससे युवाओं को लंबे समय तक रिजल्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

जिला स्तर की भर्तियां भी होंगी केंद्रीकृत

सरकार जिला स्तर पर होने वाली चतुर्थ श्रेणी और अन्य भर्तियों को भी कर्मचारी चयन मंडल के अधीन लाने की तैयारी में है। इससे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि कई राज्यों के भर्ती बोर्डों का अध्ययन करने के बाद यह मॉडल तैयार किया गया है। उनका कहना है कि यह नया मंडल राज्य में समयबद्ध और पारदर्शी भर्ती प्रणाली स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

छग राज्य में काला हीरा की खेती आधुनिक तकनीक और नवाचार से

मध्यप्रदेश के किसानों का ग्राम लिंगाडीह आरंग में मखाना खेती का भ्रमण और प्रशिक्षण कार्य हुआ संपन्न

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

धान के कटोरे कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अब एक नई फसल अपनी पहचान बना रही है - सुपर फूड मखाना, जिसे काला हीरा भी कहा जाता है। स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर मखाने की खेती अब राज्य में आधुनिक तकनीक और नवाचार के साथ हो रही है।

मखाना उत्पादन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर एवं अध्यक्ष जनपद सदस्य आरंग, रिंकू चंद्राकर ने की। मध्य प्रदेश के किसानों सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि चंद्रहास चंद्राकर ने कहा की केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से छत्तीसगढ़ मखाना बोर्ड सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम में शामिल हुआ है इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मुख्य मंत्री विष्णु देव साय कृषि मंत्री राम विचार नेताम के द्वारा मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने विशेष प्रयास किया जा रहा है।

श्री चंद्राकर ने कहा की छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम व्यवसायिक उत्पादन आरंग ब्लॉक के ग्राम लिंगाडीह के किसान स्व. कृष्ण कुमार

चंद्राकर द्वारा प्रारंभ किया गया था। राज्य का प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन 5 दिसंबर 2021 को ग्राम लिंगाडीह में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। अब मखाना उत्पादन में प्रदेश में आरंग का नाम अपनी अलग पहचान बना चुका है।

कार्यक्रम के अध्यक्ष जनपद सदस्य रिंकू चंद्राकर ने कहा किया हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम मखाना उत्पादन एवं संस्करण केंद्र हमारे क्षेत्र ग्राम लिंगाडीह में स्थापित हुआ है। छटेरा, निसदा एवं अन्य गांव में भी इसके विस्तार हेतु प्रयास किया जा रहे हैं हमारे इस केंद्र में न केवल हमारे प्रदेश के बल्कि अन्य प्रदेश के लोग भी यहां मखाना की खेती सीखने आ रहे हैं जो हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है।

मध्य प्रदेश के उमरिया जिला से 50 किसानों का एक भ्रमण दल कृषि विभाग के द्वारा मखाना की खेती के भ्रमण हेतु रायपुर जिला के आरंग ब्लॉक स्थित ओजस फॉर्म का भ्रमण किया। इस दौरान किसानों ने मखाना की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और अपने अनुभव साझा किए।

राष्ट्रीय मखाना महोत्सव 2024 एवं 2025 में सम्मानित मखाना उत्पादक किसान एवं ओजस फार्म दाऊजी मखाना के प्रबंधक संजय नामदेव ने मखाना की खेती के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रति एकड़ में 20 किलो बीज की आवश्यकता होती है और उत्पादन लगभग 10 क्विंटल के आसपास प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि 6 माह की अवधि वाले फसल में किसी भी प्रकार का कीट व्याधि का प्रकोप नहीं होता है और न ही किसी प्रकार की चरी और चोरी की समस्या रहती है। इंदिरा गाँधी कृषि विश्व विद्यालय के सब्जी विज्ञान के पीएचडी छात्र डॉ. योगेंद्र चंदेल ने किसानों को मखाना की खेती के लिए आवश्यक तकनीक और संसाधनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मखाना की खेती तालाब एवं खेत दोनों विधि से की जाती है अधिकतम उत्पादन के लिए धान की तरह खेत की मताई 1 मीटर की दुरी पर 55 दिन के नर्सरी की 4000 पौधो की रोपाई एक मीटर पौधा से पौधा एवं कतार से कतार की दुरी पर रोपाई समय समय पर नींदाई खाद प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करने पर अधिकतम उत्पादन मिलता है मखाना की खेती प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए हमारे द्वारा किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाती है।

ICAR-CIPHET (केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान), लुधियाना, पंजाब से प्रशिक्षण प्राप्त शिव नारायण साहू ने मखाना के प्रोसेसिंग की जानकारी देते हुए बताया कि 1 किलो मखाना के बीज से लगभग 200 से 250 ग्राम पॉप प्राप्त होता है, जिसकी बाजार में कीमत 700 से लेकर 1000 तक होती है। उन्होंने बताया कि यदि किसान मखाना का उत्पादन कर स्वयं प्रसंस्करण कर पैकेजिंग करके भेजते हैं तो प्रति एकड़ अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है।

इस भ्रमण के दौरान किसानों ने मखाना की खेती के बारे में शिव साहू से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि मखाना की खेती से उन्हें अच्छा मुनाफा हो सकता है और यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। कृषि विज्ञान के अधिकारियों ने बताया कि मखाना बोर्ड से इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को मखाना की खेती के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाती है, और उन्हें इसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है।

इस भ्रमण में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से भ्रमण दल प्रभारी दहायत एवं भ्रमण दल में शामिल किसानों ने बताया कि वे मखाना की खेती के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्साहित हैं और इसे अपने खेतों में अपनाने के लिए तैयार हैं।

प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री

भेंट

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने मुख्यमंत्री से की सौजन्य मुलाकात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी प्रशिक्षु न्यायाधीशों को न्यायिक सेवा में चयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और सशक्त स्तंभ है। आने वाले समय में आप सभी के कंधों पर समाज और न्याय व्यवस्था से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आप सभी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए इन जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि न्यायपालिका आमजन के अधिकारों की रक्षा और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। इस अवसर पर विधि विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सांवत, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की संचालक श्रीमती निधि शर्मा तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

संपादकीय

नियमों का पालन करने को कहना, पक्षपात नहीं है

लोकतंत्र में संसद का अपना अहम स्थान है ।यहां देश के चुने हुए प्रतिनिधि देश के लिए जरूरी कानून बनाते हैं,देश की गंभीर समस्याओ ? पर चर्चा करते हैं, समाधान का प्रयास करते हैं। यह सब करने के लिए नियम बने हुए हैं इसलिए लोकसभा अध्यक्ष सबसे से संसद के भीतर नियमों का पालन करते हुए अपनी बात कहने को कहते हैं। इससे संसद में व्यवस्था बनी रहती है और सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता है और सभी अपनी बात को नियमों के अनुसार कहते हैं और सार्थक बहस हो पाती है। अध्यक्ष किसी भी दल का रहे उसका काम होता है संसद के भीतर जो कुछ हो नियमों के अनुसार हो, ताकि संसद में व्यवस्था बनी रही,संसद की गरिमा बनी रहे। देश के लोगों को पता रहे कि उसके जनप्रतिनिधि उनके हित में संसद के भीतर क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं।

अध्यक्ष यदि नेता प्रतिपक्ष या किसी सदस्य को नियमों का पालन करने को कहता है तो यह किसी के साथ पक्षपात करना नहीं होता है। अध्यक्ष का काम है यदि कोई सदस्य नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे बताना कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष नियमों का पालन न करवाए तो संसद में कौन क्या कह रहा है इसका तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि सब के सब एक साथ कहेंगे तो संसद में किसने क्या कहा कैसे पता चलेगा क्योंकि शोर में तो किसी की बात सुनी नहीं जा सकती। इसलिए संसद में जब कोई सदस्य कुछ कहता है तो उसका माइक चालू कर बाकी लोगों का माइक बंद रहता है। माइक बंद रहता है तो यह नियम के अनुसार रहता है। सब जानते हैं कि माइक बंद रहता है तो कब बंद रहता है लेकिन लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाना है तो कह दिया जाता है उनका माइक बंद कर दिया जाता है ।विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है। विपक्ष के साथ भेदभाव किया जाता है।

अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान तरुण गोगोई ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एलओपी राहुल गांधी को 20 बार बोलने से रोका। यह सच है कि राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 20 बोर टोका। गोगोई तो उतना ही सच बता रहे हैं जिससे उनका आधा सच लोगों को पूरा सच लगे. देश के लोगों को लगे कि हां गोगोई सच कर रहे हैं कि राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोका गया है लेकिन गोगोई यह सच नहीं बताते हैं कि अध्यक्ष बिरला ने उनको बोलने से 20 बार मना किया तो क्यों मना किया। बिरला ने राहुल गांधी को बोलने से इसलिए मना किया वह नियमों के विपरीत बोलने का प्रयास कर रहे थे और बिरला उनको बता रहे थे कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। संसद में कोई भी सदस्य चाहे वह राहुल गांधी हों या और कोई यदि वह नियमों का पालन नहीं करेगा तो अध्यक्ष तो उसे बताएंगे ही कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

आज सब जानते हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो कुछ कहना चाह रहे थे वह नियमों के अनुरूप नहीं था, संसद में किसी किताब को कोई हिस्सा तब ही पढ़ा जा सकता है,जब वह प्रकाशित हो और उसे संसद में रखा जा सके। राहुल गांधी ऐसी किताब को कोई हिस्सा पढ़ना चाह रहे थे जो प्रकाशित ही नहीं हुआ था। राहुल गांधी को गांधी परिवार से होने के कारण बड़ा घमंड और इसी वजह से जब भी उनको अध्यक्ष किसी वजह से रोकते है और टोकते हैं तो उनको बुरा लगता है और उनके आसपास के लोगों को और बुरा लगता है कि आप राहुल गांधी को कैसे रोक या टोक सकते हो। यानी अध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और गांधी परिवार से है इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है जैसा व्यवहार दूसरे आम सदस्यों के साथ किया जाता है।

यही वजह है कि कांग्रेस सहित विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और बहस में फिर से यह बात कही कि वह विपक्ष से भेदभाव करते हैं। यह एक तरह से ओम बिरला को डराने का प्रयास है, दबाव में लाने का प्रयास है कि हम आपको पद से हटा तो नहीं सकते लेकिन आपको बदनाम जरूर कर सकते हैं आप हमारे साथ भेदभाव करते हैं। गांधी परिवार से होने का राहुल गांधी को जितना घमंड है गांधी परिवार में किसी को नहीं है। यह बात तो गांधी परिवार के कई सदस्यों के आचरण को देखते हुए कहा जा सकता है। यही वजह है कि किरण रिजिजू ने बहस के दौरान यह बात जानबूझकर कही कि राहुल गांधी पं.नेहरू व राजीव गांधी से क्यों नहीं सीखते संसदीय मर्यादा ताकि यह साबित किया जा सके कि राहुल गांधी ही गांधी परिवार के ऐसे सदस्य है जो संसदीय मर्यादा का पूरा ख्याल नहीं रखते हैं।

आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करा आत्मनिर्भर बनी संगीता सिंह

धनंजय राठौर सयुक्त संचालक, जनसंपर्क, लोकेश्वर सिंह सहायक जनसंपर्क अधिकारी

स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे महिलाएं छोटी-छोटी आजीविका गतिविधियां (जैसे- खेती, पशुपालन, सिलाई, आधार से जुड़ी सेवाएं) शुरू कर सकें। इस मिशन के अंतर्गत महिलाएं सशक्त बनकर न केवल परिवार की आय में वृद्धि कर रही हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भर होकर सामाजिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जब महिलाओं को सही अवसर, संसाधन और मार्गदर्शन मिलता है, तो वे न केवल अपने जीवन में बदलाव लाती हैं बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिला मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम दुधाशी की निवासी श्रीमती संगीता सिंह की कहानी भी महिला सशक्तिकरण की ऐसी ही प्रेरक मिसाल है, जिन्होंने अपने परिश्रम और आत्मविश्वास से एक नई पहचान बनाई है।

बीसी सखी के रूप में शुरू हुआ सफर

संगीता सिंह ने वर्ष 2021 में बीसी सखी के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की। उनके माध्यम से गांव के लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलने लगा। पहले जहां ग्रामीणों को पैसे निकालने या बैंक से जुड़े कार्यों के लिए दूर शहर या ब्लॉक मुख्यालय तक जाना पड़ता था, वहीं अब यह सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध होने लगीं। इससे ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों बचने लगा और गांव के लोगों को बड़ी सुविधा मिली।

स्वयं सहायता समूह से मिली आर्थिक मजबूती

संगीता सिंह बताती हैं कि उन्होंने बिहान योजना के अंतर्गत अपने स्वयं सहायता समूह से 68 हजार रुपये का ऋण लिया था। इसी आर्थिक सहयोग से उन्होंने बीसी सखी के रूप में अपना कार्य शुरू किया। शुरुआत में कई चुनौतियां सामने आईं, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और सेवा भावना से उन्होंने धीरे-धीरे गांव के लोगों का विश्वास जीत लिया। आज गांव के लोग उन्हें भरोसे के साथ अपनी बैंकिंग सेवाओं के लिए संपर्क करते हैं।

उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला आधार किट

संगीता सिंह के समर्पण और उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन को देखते हुए मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर के जिला प्रशासन ने उन्हें नई जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया। आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में आधार सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से जिले में पांच नए आधार केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी पहल के तहत संगीता सिंह को लैपटॉप सहित आधार किट प्रदान की गई। जिला प्रशासन की ओर से ईडीएम नारायण केवर्त ने उन्हें यह आधार किट सौंपा।

अब गांव में ही मिलेंगी आधार सेवाएं

आधार किट मिलने के बाद संगीता सिंह अब अपने गांव के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगी। इनमें नया आधार पंजीयन, आधार अपडेट तथा अन्य आवश्यक कार्य शामिल हैं। इससे ग्रामीणों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए शहर या ब्लॉक मुख्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें अपने गांव के पास ही सुविधाएं मिल सकेंगी।

अन्य महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा

संगीता सिंह की सफलता की कहानी पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता यह दर्शाती है कि यदि महिलाओं को अवसर और सहयोग मिले तो वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। उनकी उपलब्धि यह भी साबित करती है कि महिलाएं केवल अपने परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम

जिला प्रशासन की यह पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को भी मजबूत कर रही है। संगीता सिंह जैसी महिलाएं आज ग्रामीण भारत में बदलाव की नई कहानी लिख रही हैं। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि आत्मविश्वास, परिश्रम और सही अवसर मिल जाए तो कोई भी महिला अपने सपनों को साकार कर सकती है। बिहान योजना का उद्देश्य गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए मजबूत संस्थाएं बनाकर और उन्हें वित्तीय और आजीविका सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करके गरीबी कम करने को बढ़ावा देना है।

तेल की राजनीतिः अंतर्राष्ट्रीयता में एक बड़ा बदलाव

तेल की राजनीति उन्नीसवीं सदी और बीसवीं सदी की शुरुआत में, इंपीरियलिज़्म का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशन पर हावी था। ताकतवर देशों ने कच्चा माल निकालने, मार्केट बढ़ाने और पॉलिटिकल असर बढ़ाने के लिए कमजोर इलाकों पर अपना कंट्रोल बढ़ाया। हालांकि, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइजेशन की लहर के बाद, ट्रेडिशनल इंपीरियलिज़्म – जिसकी पहचान सीधे पॉलिटिकल कंट्रोल से होती थी – काफी कम हो गया। इसकी जगह, ग्लोबल पावर स्ट्रगल का एक नया और ज़्यादा बारीक रूप सामने आयाः ऑयल पॉलिटिक्स। पेट्रोलियम रिसोर्स, प्रोडक्शन रूट और एनर्जी मार्केट पर कंट्रोल इंटरनेशनल रिलेशन को तय करने वाले सबसे जरूरी फैक्टर में से एक बन गया है। कई तरह से, ऑयल पॉलिटिक्स ने अलायंस, झगड़े और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को आकार देकर इंपीरियलिज़्म के पुराने कॉन्सेप्ट की जगह ले ली है।

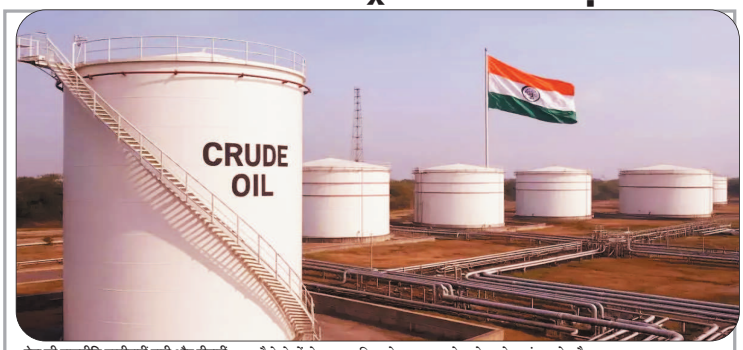

ऑयल को अक्सर मॉडर्न सिविलाइजेशन की लाइफब्लड कहा जाता है। मॉडर्न इकॉनमी ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, बिजली बनाने और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पेट्रोलियम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। इस डिपेंडेंस की वजह से, जिन देशों के पास बड़े ऑयल रिजर्व हैं, वे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। साथ ही, जिन देशों में काफी एनर्जी रिसोर्स नहीं होते, वे अक्सर डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और कभी-कभी मिलिट्री तरीकों से स्टेबल ऑयल सप्लाई पाने की कोशिश करते हैं। एनर्जी रिसोर्स के लिए इस जबरदस्त मुकाबले ने पावर रिलेशन का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया है जो क्लासिकल इंपीरियलिज़्म के पीछे के मकसद से काफी मिलता-जुलता है।

2,000 करोड़ के घाटे ने उएड पीटर एल्बर्स को नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया ऑयल पॉलिटिक्स की सबसे जरूरी बातों में से एक है तेल से अमीर इलाकों, खासकर मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटेजिक अहमियत। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों के पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल के पक्के रिजर्व हैं। ये रिजर्व इस इलाके को दुनिया भर की पॉलिटिकल अटेंशन का सेंटर बनाते हैं। बड़ी ताकतें—जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, रूस और यूरोपियन देश शामिल हैं— हिस्टॉरिकली एनर्जी रिसोर्स तक पहुँच पक्की करने के लिए मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में गहराई से शामिल रही हैं। उनके शामिल होने में अक्सर मिलिट्री अलायंस, हथियारों की बिक्री, इकोनॉमिक मदद और डिप्लोमैटिक दखल शामिल होते हैं।

तेल और इंटरनेशनल पावर के बीच का रिश्ता बीसवीं सदी के दौरान खास तौर पर साफ हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन और मशीनी लड़ाई ने पेट्रोलियम की माँग को बहुत बढ़ा दिया। दोनों वर्ल्ड वॉर के दौरान, मिलिट्री कामयाबी के लिए तेल तक पहुँच बहुत जरूरी थी। वॉर के बाद, ऑटोमोबाइल, एविएशन और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के तेजी से बढ़ने से तेल और भी जरूरी हो गया। इस वजह से, ग्लोबल ताकतें नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तेल सप्लाई पर कंट्रोल को जरूरी मानने लगीं।

मल्टीनेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन की भूमिका से भी ऑयल पॉलिटिक्स साफ हो गई। बड़ी एनर्जी कंपनियों ने ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर में पेट्रोलियम की खोज, निकालने, रिफाइन करने और बांटने में अहम भूमिका निभाई है। कई डेवलपिंग देशों में, इन कॉर्पोरेशन ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और नीतियों पर काफी असर डाला है। आलोचकों का तर्क है कि यह आर्थिक असर इंपीरियलिज़्म के एक मॉडर्न रूप को दिखाता है, जिसे अक्सर नियो-इंपीरियलिज़्म कहा जाता है, हालांकि इसका कारण बताना सही नहीं है। सीधे कॉलोनियल शासन के बजाय, ताकतवर देश और कॉर्पोरेशन कीमती संसाधनों पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए आर्थिक फायदे और टेक्नोलॉजिकल बेहतरी का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल पॉलिटिक्स में एक बड़ा मोड़ 1973 में तेल संकट के दौरान आया।

ऑर्गनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (डढएउ) के सदस्यों ने मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल झगड़ों के जवाब में कई पश्चिमी देशों पर ऑयल बैन लगा दिया। इस बैन की वजह से तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई और कई इंडस्ट्रियलाइज़्ड देशों में गंभीर आर्थिक रुकावटें आईं। इस घटना ने दिखाया कि कैसे तेल बनाने वाले देश एनर्जी संसाधनों को एक ताकतवर पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसने यह भी दिखाया कि ऑयल मार्केट पर कंट्रोल ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर असर डाल सकता है। ऑयल पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल झगड़ों से भी गहरा नाता रहा है। कई युद्ध और पॉलिटिकल संकट पेट्रोलियम रिसोर्स की स्ट्रेटेजिक अहमियत से प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए, फारस की खाड़ी इलाके में झगड़ों में अक्सर ऑयल रिजर्व और सप्लाई रूट को लेकर चिंताएँ रही हैं।

होर्मुज स्ट्रेट जैसे समुद्री चोकपॉइंट को सुरक्षित करना, जिससे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल गुजरता है, कई ग्लोबल ताकतों के लिए एक मुख्य प्राथमिकता बनी हुई है। इसलिए, पाइपलाइन, रिफाइनरी और शिपिंग लेन की सुरक्षा मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का एक अहम पहलू बन गई है। ऑयल पॉलिटिक्स का एक और जरूरी पहलू यह है कि इससे आर्थिक निर्भरता पैदा होती है। कई डेवलपिंग देश जिनके पास बड़े ऑयल रिजर्व हैं, वे सरकारी रेवेन्यू के लिए पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। जबकि ऑयल वेल्थ आर्थिक ग्रोथ ला सकती है, यह करप्शन, पॉलिटिकल अस्थिरता और वेल्थ के असमान डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चुनौतियाँ भी पैदा कर सकती है। इस घटना को अक्सर रिसोर्स कर्स कहा जाता है। जो देश ऑयल एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, वे ग्लोबल ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बाहरी पॉलिसियों के प्रति कमजोर हो सकते हैं।

मिलेट्स की खेती से बढ़ रही किसानों की आय

दंतेवाड़ा में रागी उत्पादन की नई पहल

नई दृष्टिबिंदु / दंतेवाड़ा

मिलेट्स (मोटा अनाज) की खेती कम लागत, कम पानी और बिना रसायनों के होने वाली एक अत्यधिक लाभदायक व पौष्टिक खेती है, जो 80-90 दिनों (जून-जुलाई से) में तैयार होती है। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी जैसे मिलेट्स बंजर या कम उपजाऊ भूमि के लिए भी उपयुक्त हैं। दंतेवाड़ा जिला अब मिलेट्स उत्पादन के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले में मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की जा रही है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग के प्रयासों से अब किसान पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं। इससे किसानों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मदद मिल रही है।

दंतेवाड़ा जिले के कृषि इतिहास में पहली बार लगभग 300 प्रगतिशील किसान उन्नत श्री विधि से रागी (मडिया) की खेती कर रहे हैं। इस नई पद्धति से रागी उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ पोषक अनाजों की खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। रागी को पोषण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने किसानों में उत्साह

इस पहल को सफल बनाने के लिए कृषि विभाग और भूमगादी की टीम गांव-गांव जाकर किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दे रही है। किसानों को बुवाई की सही विधि, पौधों के बीच उचित दूरी, जैविक खाद का उपयोग और फसल प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। इससे किसानों में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के प्रति उत्साह बढ़ रहा है।

जैविक और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने किसानों को बहुफसली प्रणाली अपनाने किया जा रहा है प्रेरित

श्री विधि से रागी की खेती कई तरह से लाभदायक मानी जाती है। इस पद्धति में बीज कम लगता है, जिससे लागत घटती है। साथ ही पारंपरिक खेती की तुलना में पानी की आवश्यकता भी कम होती है, जो वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए काफी उपयोगी है। पौधों को पर्याप्त जगह मिलने से उनका बेहतर विकास होता है और उत्पादन बढ़ने की संभावना रहती है। यह पद्धति जैविक और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है।

दंतेवाड़ा जिले में रागी के साथ-साथ कोदो-कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन और तिलहन जैसी अन्य फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि विभाग किसानों को बहुफसली प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि उनकी आय के स्रोत बढ़ सकें और खेती अधिक टिकाऊ बन सके। इस पहल से दंतेवाड़ा के किसान पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संतुलित उपयोग करते हुए कृषि में नई पहचान बना रहे हैं। मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिलने से न केवल किसानों की आय बढ़ने की संभावना है, बल्कि पोषण सुरक्षा और टिकाऊ कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

सू- दोकू क्र.340

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.339 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

साझी मेहनत, साझा समृद्धि – बिहान से बदल रहा ग्रामीण महिलाओं का जीवन

नई दृष्टिबिंदु / धमतरी

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त अभियान बन चुका है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसालें गढ़ रही हैं।

बिहान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वसहायता समूहों के माध्यम से संगठित कर उन्हें स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर समाज में आत्मगौरव के साथ जीवन यापन कर सकें। धमतरी जिले में बिहान योजना के तहत बीते जुलाई माह तक 58 महिला सदस्यों को सेंट्रिंग प्लेट निर्माण एवं किराये हेतु ऋण प्रदाय किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने स्वरोजगार की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाया है। इनमें धमतरी विकासखंड की 27, कुरूद की 15, मगरलोड की 7 एवं नगरी विकासखंड की 9 महिलाएं शामिल हैं। इन महिलाओं को समूह स्तर पर प्रकरण तैयार कर आरएफ मद से 15 हजार, सीआईएफ से 60 हजार तथा बैंक ऋण के रूप में 3 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई।

प्राप्त राशि से समूह की महिलाओं द्वारा 59 हजार 300 वर्गफीट सेंट्रिंग प्लेट की खरीदी की गई है। इन प्लेटों को महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सहित अन्य शासकीय निर्माण कार्यों और स्थानीय बाजारों में 20 से 25 रुपये प्रति वर्गफीट के किराये पर उपलब्ध करा रही हैं। इससे महिलाओं को निरंतर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो रही है।

महिलाओं ने समूह की सहायता से न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि नियमित बचत कर समय पर ऋण की अदायगी भी कर रही हैं। इस पहल से उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है।

जिला पंचायत धमतरी द्वारा इन समूहों को न केवल आर्थिक सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान से भी उन्हें सशक्त बनाया गया। बिहान योजना से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। समूह आधारित कार्य प्रणाली ने उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाया है। आज वे स्वयं की मेहनत से अपने परिवार और समाज में परिवर्तन की प्रेरणा बन रही हैं।

बिहान योजना ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब महिलाएं संगठित होकर आगे बढ़ती हैं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवचेतना और विकास की नई राहें खुलती हैं।

कल राष्ट्रीय लोक अदालत : मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने तैयारियों की समीक्षा की

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत (14 मार्च 2026) की तैयारियों की समीक्षा वर्चुअल बैठक के माध्यम से की। बैठक में राज्य के सभी प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष-सचिव, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा श्रम न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हुए। इस अवसर पर न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल, कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति भी उपस्थित रहे।

मुख्य न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों से अपील की कि विशेष प्रयास करते हुए अधिकतम संख्या में पुराने लंबित सिविल एवं आपराधिक सुलह योग्य मामलों की पहचान कर उनका समाधान किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) तथा मोटर दुर्घटना

क्षतिपूर्ति से जुड़े मामलों पर प्राथमिकता से ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारी लोक अदालत से पूर्व पक्षकारों को समझाइश देकर मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि न्यायिक अधिकारी बीमा और वित्तीय कंपनियों जैसे संस्थागत पक्षकारों वाले मामलों की पहचान कर उनके साथ समन्वय स्थापित करें, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समझौते के माध्यम से निपटारा हो सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। यह लोक अदालत उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, परिवार न्यायालय, विभिन्न फोरम, अधिकरण तथा सभी राजस्व न्यायालयों में एक साथ आयोजित होगी। इसमें सिविल और आपराधिक सुलह योग्य मामलों सहित विभिन्न प्रकार के विवादों का समाधान किया जाएगा। वहीं सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों का निपटारा मोहल्ला लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।

जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक कुल 41,19,609 मामलों की पहचान की गई है। इनमें 40,21,821 पूर्व-वाद मामले तथा 97,788 न्यायालयों में लंबित मामले शामिल हैं, जिनमें पक्षकारों के बीच सुलह की संभावनाएं तलाश कर समाधान की प्रक्रिया जारी है।

संगीता को मिला महतारी वंदन योजना का लाभ, अब आसानी से निभा पा रही पारिवारिक जिम्मेदारी

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में विभिन्न प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ वे आत्मनिर्भर भी बन रही हैं।

ऐसी ही कहानी है मानपुर विकासखंड के ग्राम सरोली निवासी संगीता की, जिनके जीवन में महतारी वंदन योजना ने बड़ी राहत प्रदान की है। संगीता एक साधारण गृहिणी हैं, जो पहले अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में कई चुनौतियों का सामना करती थीं। लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली 1000 रुपए की मासिक सहायता राशि ने उनके जीवन को काफी हद तक आसान बना दिया है।

हर महीने मिलने वाली इस राशि से संगीता अब घर के छोटे-मोटे खर्च आसानी से पूरा कर पा रही हैं। वे इस सहायता राशि का उपयोग घर के लिए राशन सामग्री खरीदने और साप्ताहिक बाजार से आवश्यक सामान तथा सब्जियां लेने में करती हैं। पहले उन्हें इन जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती थी और कई बार पति की आय पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब महतारी वंदन योजना की सहायता राशि उनके लिए बड़ा सहारा बन गई है। संगीता बताती हैं कि इस योजना ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक तंगी को कम किया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर दिया है। अब वे अपनी दैनिक जरूरतें स्वयं पूरी कर पा रही हैं, जिससे उनके परिवार को एक स्थिर और बेहतर जीवन मिल रहा है।

हितग्राही संगीता ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना से उन्हें और उनके परिवार को काफी मदद मिली है। अब वे अपने बच्चों और घर की आवश्यकताओं को बिना किसी परेशानी के पूरा कर पा रही हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री साय को धन्यवाद दिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन

कवर्धा। कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत प्याज के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत ग्राम गांगपुर में कृषक प्रशिक्षण सह प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन 10 मार्च को किया गया। उक्त कार्यक्रम 35 एकड़ रकबा में संचालित प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें योजनांतर्गत लाभान्वित कृषकों को प्याज की उन्नत किस्म भीमा किरण का बीज तथा पौध संरक्षण के लिए आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के पूर्व कृषकों को प्याज की उन्नत खेती की वैज्ञानिक पद्धति, उन्नत किस्मों के चयन, रोपण विधि, पोषक तत्व प्रबंधन तथा रोग एवं कीट नियंत्रण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

फर्जी और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर बिलासपुर पुलिस का सराहनीय कार्रवाई

अब पेट्रोल पंपों पर भी नहीं मिलेगा वाहनों में ईंधन, पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

पुलिस ने गलत, फर्जी और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। ऐसे वाहनों को अब पेट्रोल-डीजल भी नहीं मिलेगा। पुलिस ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि संदिग्ध या बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन न दें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। जिले में फर्जी, गलत या बिना नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले वाहनों पर अब पुलिस की नजर और सख्त हो गई है। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के साथ अब पेट्रोल-डीजल पंपों पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाले वाहनों को अब पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा।

उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहनों के माध्यम से होने वाली संभावित आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जिलेभर में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से चेकिंग पॉइंट लगाकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बीट पुलिस के माध्यम से सभी थाना क्षेत्रों में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

नंबर प्लेट में गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई

यातायात पुलिस के मुताबिक जिन वाहनों में नंबर प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की गई है, अमानक नंबर प्लेट लगी है या किसी अन्य वाहन का नंबर लिखकर वाहन चलाया जा रहा है, ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकता है और संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

पेट्रोल पंपों को दी गई सख्त हिदायत

यातायात पुलिस ने जिले के सभी पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन न दिया जाए। यदि ऐसे वाहन पंप पर पहुंचते हैं तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या संबंधित थाने को सूचना देने के लिए कहा गया है।

अपराध व हादसों के रोक पर कदम

पुलिस का कहना है कि फर्जी या गलत नंबर प्लेट वाले वाहन न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि कई बार गंभीर अपराधों और सड़क हादसों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे मामलों में वाहन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

आम नागरिकों से पुलिस की अपील

यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाले वाहन दिखाई दें तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस या नजदीकी थाने को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

नारी शक्ति, आत्मविश्वास व सहनशीलता का प्रतीक : चन्द्रप्रकाश चन्द्रवंशी

सम्मान

नपा अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कर्मचारियों का किया सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर पालिका परिषद कवर्धा के सभाकक्ष में आयोजित महिला सम्मान समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने अपने टीम के साथ स्वच्छता दीदीयों का आरती कर पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। उन्होंनें सभाकक्ष में साथ बैठकर नास्ता किया तथा नारी शक्ति की महानता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया व जिस जगह में बैठे रहे वहां जाकर उनका सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई व शुभकामनाएं देकर पैर छूकर प्रणाम किया।

नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रवंशी ने कहा कि नारी शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, प्रेम, त्याग, और सहनशीलता का प्रतीक है नारी समाज की नींव है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है सभी महिलायें काबिल और मेहनती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई प्रावधान किये हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में महतारी वंदन योजना के साथ साथ अनेक योजनाएं लागू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा और हौसला देता है। मातृ शक्ति ने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है और अपनी क्षमता और प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है।

नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि महिलायें आज के समय पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिला दिवस का दिन हमें नारी की हर छोटी-बड़ी लड़ाई को सम्मान देने और उनके सपनों को पंख देने का मौका देता है। आज का दिन महिलाओं द्वारा समाज में दिए गए योगदान, उनके संघर्ष तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाता है। इस दिन उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि वह हमारे लिए कितनी खास हैं।

अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष पवन जायसवाल, पार्षद अजय ठाकुर, बिहारी राम धुर्वे, योगेश चंद्रवंशी, सौखी आहिरवार, डोनेश राजपूत, दीपक सिन्हा सहित अधिक संख्या में महिला दीदी उपस्थित रहे है।

कवर्धा में सवर्ण समाज की महापंचायत 15 मार्च को

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कवर्धा में 15 मार्च 2026 को सवर्ण समाज की महापंचायत आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम सवर्ण एकता मंच के बैनर तले आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हाल ही में सवर्ण एकता मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर महापंचायत की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। मंच से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि जिले के 13 सवर्ण समाज इस मंच से जुड़े हुए हैं और सभी संगठनों की सहमति से महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर चिंता जताते हुए इसे सवर्ण समाज के विद्यार्थियों के भविष्य के लिए प्रतिकूल बताया। संगठनों ने एकमत से इस रेगुलेशन को वापस लेने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग उठाई। इसी मांग को लेकर महापंचायत के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है।

सवर्ण एकता मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि महापंचायत का उद्देश्य सवर्ण समाज की एकता को मजबूत करना और विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना है। कार्यक्रम के लिए मुख्य नारा ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया, मिलकर बदलो अपनी दुनिया रखा गया है। बैठक में सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, मंच के सदस्य और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजकों ने समाज के सभी लोगों से महापंचायत को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।

राजनांदगांव के लाइनमैन ईश्वरी लाल वर्मा दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित

उपलब्धि

केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री नाईक ने दिया सर्वश्रेष्ठ लाइनमैन का पुरस्कार

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राजनांदगांव जिले के मुसराकला वितरण केन्द्र में कार्यरत ईश्वरी लाल वर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत पर्यावास केन्द्र (क्स्र्ञ्लुं३३ उीह्ल३१), लोधी रोड में आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाईक द्वारा वर्मा को देश भर से चयनित चुनिंदा लाइनमैनों के बीच सर्वश्रेष्ठ लाइनमैन के गौरवपूर्ण सम्मान से विभूषित किया गया। इस अवसर केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री के द्वारा वर्मा को प्रशस्ति पत्र, शाल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि डोंगरगढ़ संभाग के मुसराकला वितरण केन्द्र में पदस्थ लाइनमैन ईश्वरी लाल वर्मा को यह राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में अटूट कर्तव्यनिष्ठा, उच्च तकनीकी दक्षता और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया है। विशेष रूप से, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रिकॉर्ड सोलर कनेक्शन प्रदान करने में उनके असाधारण योगदान की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई।

विभागीय नेतृत्व ने व्यक्त की खुशी

वर्मा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव

एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी भीमसिंह कंवर ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मंच पर यह सम्मान मिलना छत्तीसगढ़ की विद्युत सेवाओं की गुणवत्ता और हमारे कमर्चारियों के समर्पण का प्रमाण है। यह सम्मान न केवल ईश्वरी लाल वर्मा की व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि यह प्रदेश के हजारों बिजली कमिर्यो के मनोबल को बढ़ाने वाला एक मील का पत्थर साबित होगा।

राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक शिरीष सेलट एवं राजनांदगांव वृत के अधीक्षण अभियंता शंकेश्वर कंवर ने भी वर्मा को उनकी उत्कृष्ट कायशैली के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उन्होंने कहा कि मुसराकला जैसे ग्रामीण अंचल से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना गौरव की बात है।

पेंडाकोडो स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन

लक्ष्य निर्धारित कर नियमित अभ्यास करें, सफलता अवश्य मिलेगी-नम्रता सिंह

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह के मुख्य आतिथ्य में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पेंदाकोडो में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद सदस्य श्री महेश कुंजाम, जनप्रतिनिधि श्री रमेश हिड़मे, राजेंद्र जुरेशिया, हेमंत नेताम, ओमप्रकाश शिक्षकगण स्थानीय जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, विभागीय अधिकारी, शिक्षक, पालक तथा बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का समय प्रतिस्पर्धा का है, इसलिए सभी को अपना लक्ष्य निर्धारित कर नियमित अभ्यास करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और वतर्मान समय में करियर के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। अपनी रुचि के अनुसार करियर का चयन कर परिश्रम करें तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि किसी भी परिस्थिति में हार न मानें और निरंतर प्रयास करते रहें।

उन्होंने कहा कि सभी छात्राएं एक परिवार की तरह हैं, इसलिए एक-दूसरे का सहयोग करें और आगे बढ़ने के लिए एक-दूसरे को प्रेरित करें। पालकों और शिक्षकों का सम्मान करना हमारे संस्कार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे समाज में उनकी भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। अंत में उन्होंने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं।

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है, जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय आत्मनिर्माण का है, इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई करें, सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने छात्राओं से कहा कि उन्हें यहां पढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर मिला है, इसलिए पालकों के विश्वास पर खरा उतरें और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनें।

कलेक्टर ने पालकों को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की शुरुआत घर से होती है। बच्चों को घर की जिम्मेदारियों के साथ-साथ पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर ने कहा कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने छात्राओं से दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अध्ययन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी बालिकाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हुए राष्ट्र, क्षेत्र एवं समाज निर्माण में सहभागिता की बात कहीं।

बालिकाओं ने जनप्रतिनिधियों के साथ मनाया जन्मदिन

कार्यक्रम के दौरान आवासीय विद्यालय में इस माह जन्मदिन पड़ने वाली छात्राओं का जन्मदिन भी मनाया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में छात्राओं ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। विद्यालय परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला।

कलेक्टर ने नायब तहसीलदार कार्यालय तुमड़ीबोड़ का किया औचक निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कार्रवाई

राजस्व प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण के दिए निर्देश

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने नायब तहसीलदार कार्यालय तुमड़ीबोड़ का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील में दर्ज सभी राजस्व प्रकरणों के शीघ्र एवं समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश नायब तहसीलदार को दिए।

कलेक्टर यादव ने पूर्व में आदेश पारित प्रकरणों का अवलोकन किया तथा ई-कोर्ट एवं भुइयां पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पटवारी को दूरभाष के माध्यम से आदेश पारित होने के एक दिवस के भीतर राजस्व अभिलेखों में रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नायब तहसीलदार को सभी पटवारियों से समय पर पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरणों का नियमानुसार एवं निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही तहसील क्षेत्र में दर्ज सभी समय-सीमा बाह्य सीमांकन प्रकरणों का निराकरण आगामी दो दिनों के भीतर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों से उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार उपस्थित थे।

बीसीए के बाद अच्छी जॉब के लिए बेहतरीन करियर ऑप्शंस

बीसीए, एक पॉपुलर अंडरग्रेजुएट कोर्स है, जिसे कंप्यूटर साइंस और आईटी फील्ड में करियर बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, इस कोर्स को करने के बाद, आगे क्या करें सोच कर आप भी परेशान चल रहे हैं, तो चलिए हम आपको यहां बीसीए के बाद के कुछ बेहतरीन करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं।

अगर आपने अंडरग्रेजुएट कोर्स बीसीए कर लिया है और अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही, अक्सर स्टूडेंट्स बीसीए के बाद क्या करें? इस सवाल को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको इतना सोचने की जरूरत अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीसीए के बाद आपके पास करियर के कई बेहतरीन विकल्प होते हैं, जिनमें उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर में हाई-सैलरी जॉब्स शामिल हैं। सही करियर ऑप्शन का चुनाव आप अपने स्किल्स, इंटरेस्ट और करियर गोल्स के आधार पर कर सकते हैं। इसी क्रम में आइए हम आपकी दुविधा को दूर करते हैं। दरअसल, इस आर्टिकल में हम आपको बीसीए के बाद मिलने वाले टॉप करियर ऑप्शंस के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप अपने फ्यूचर के लिए सही फैसला ले सकें और आगे जाकर आप एक अच्छी जॉब व हाई सैलरी पा सकें। बीसीए के बाद बेहतरीन करियर ऑप्शंस –

MCA (Master of Computer Applications)

अगर आप अपनी तकनीकी स्किल्स को और मजबूत करना चाहते हैं, तो MCA करना एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह कोर्स आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे एडवांस्ड टॉपिक्स सिखाता है। रही बात इस कोर्स के बाद जॉब ऑप्शंस की तो आप इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, आईटी कंसल्टेंट आदि बन सकते हैं। इसमें आपको लगभग रू 5-12 लाख प्रति वर्ष का पैकेज भी मिल सकता है।

MBA (Master of Business Administration)

अगर आप मैनेजमेंट और लीडरशिप में करियर बनाना चाहते हैं, तो स्कूआपके लिए सही रहेगा। खासकर IT Management, Business Analytics और Digital Marketing में MBA करने से आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी जॉब मिल सकती है। इस जॉब में आपको शुरुआत में कम से कम रू 6-15 लाख प्रति वर्ष का पैकेज मिल सकता है।

डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में बनाएं करियर

बीसीए के बाद डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में करियर बनाना आज के समय में बहुत अच्छा विकल्प है। इस फील्ड में जॉब्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और सैलरी भी काफी अच्छी है। बीसीए करने के बाद, आप डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग डेवलपर आदि बन सकते हैं। बात अगर सैलरी पैकेज की करें तो आपको रू 8-20 लाख प्रति वर्ष का पैकेज मिल सकता है।

डिजिटल मार्केटिंग और SEO में हाथ आजमाएं

अगर आपको क्रिएटिविटी और मार्केटिंग में रुचि है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है, जो आप बीसीए करने के बाद आराम से कर सकते हैं। कंपनियां अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटर्स को हायर कर रही हैं। ऐसे में, आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, SEO एक्सपर्ट, कंटेंट मार्केटर की पोस्ट मिल सकती है। साथ ही, रू 4-12 लाख प्रति वर्ष का पैकेज मिल सकता है।

ये हैं दुनिया की 5 सबसे कठिन डिग्रियां

अगर आप अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और शानदार कमाई करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में बताए गई कठिन डिग्रियों में से किसी एक को चुन सकते हैं। हालांकि, इन डिग्रियों को हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और लगन से इन्हें पूरा करके आप अपने भविष्य को सुरक्षित और शानदार बना सकते हैं। अगर आप करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और अच्छी कमाई का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए सही डिग्री चुनना बेहद जरूरी है। दुनिया में कई डिग्रियां ऐसी हैं, जिन्हें पूरा करना आसान नहीं होता है, लेकिन एक बार हासिल करने के बाद इनका स्कोप और सैलरी पैकेज जबरदस्त मिलता है। कठिनाई के बावजूद, इन डिग्रियों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो आइए दुनिया की 10 सबसे कठिन डिग्रियों के बारे में जानते हैं, जिन्हें पाकर आप लाखों की कमाई कर सकते हैं।

बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी

अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो MBBS दुनिया की सबसे कठिन डिग्रियों में से एक मानी जाती है। इसमें लंबे समय तक पढ़ाई, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। लेकिन इस फील्ड में करियर बना लिया, तो कमाई की कोई सीमा नहीं होती।

इंजीनियरिंग

इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स काफी कठिन होता है, खासकर तब जब आप टॉप ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हों। इसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप का कॉम्बिनेशन होता है, जो इसे और भी चैलेंजिंग बना देता है।

चार्टर्ड अकाउंटेंसी

CA कोर्स दुनिया के सबसे कठिन कोर्सों में से एक है। इसमें कई स्तर के एग्जाम होते हैं और पास करने की दर भी काफी कम होती है। लेकिन अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं, तो बड़े कॉर्पोरेट हाउस में लाखों-करोड़ों के पैकेज पर जॉब पा सकते हैं या खुद की फर्म शुरू कर सकते हैं।

एस्ट्रोनॉमी और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग

अगर आपको अंतरिक्ष और विमानन विज्ञान में रुचि है, तो यह डिग्री आपके लिए है। लेकिन यह बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि इसमें गणित, भौतिकी और तकनीकी ज्ञान की गहरी समझ जरूरी होती है। नासा, इसरो जैसी एजेंसियों में काम करने का सपना देखने वालों के लिए यह एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है।

लॉ के बाद जज बनने और वकालत करने के अलावा भी हैं ढेर सारे विकल्प

लॉ में करियर लंबे समय से युवाओं के बीच पॉपुलर रहा है और अब इसमें विकल्पों के बढ़ने आपके लिए मनमाफिक विकल्प चुनना भी आसान हो गया है। दरअसल कानूनी पेचिदगियों और समाज के विस्तार के चलते कानून के जानकार प्रोफेशनल्स की जरूरत हर जगह बढ़ गई है। आज के समय में आम लोगों अपने अधिकारों के प्रति काफी जागरूक हैं, वे कानूनी प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं, ऐसे में लॉ में करियर बनाने वालों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही हर दिन किसी नई खोज या तकनीकी विकास के चलते पुराने और प्रचलित कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होती है। और इस लिहाज से भी कानून के जानकारों की मांग में में इजाफा हुआ है।

लॉ का ये है पाठ्यक्रम

लॉ से सम्बंधित 2 पाठ्यक्रम होते हैं पहला, 10+2 के बाद पांच वर्षीय इंटिग्रेटेड लॉ पाठ्यक्रम और ग्रेजुएशन के बाद तीन वर्षीय लॉ पाठ्यक्रम। पांच वर्षीय इंटिग्रेटेड लॉ पाठ्यक्रमों में भी अब पाँच प्रकार के पाठ्यक्रम हो गए हैं – आर्ट्स के छात्रों के लिए बीए एलएलबी, साइंस के छात्रों के लिए बीएससी एलएलबी, कॉमर्स के छात्रों के लिए बीकॉम एलएलबी, कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए बीसीए एलएलबी और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए बीबीए एलएलबी। उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपको क्लैट यानि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट से गुजरना होगा, जो वर्ष में एक बार होता है। आपकी रैंकिंग के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट किए जायेंगे। देश में कई ऐसे सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जहाँ केवल लॉ की ही पढ़ाई होती है। ग्रेजुएशन के बाद के लॉ पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए विश्वविद्यालय अपना-अपना एंट्रेंस टेस्ट संचालित करते हैं।

इस तरह बनें लायर

वह समय खत्म हो गया, जब आप लॉ की परीक्षा पास कर काला कोट पहन कर सीधे वकालत में सकते हैं। लॉ के बाद आपको बार काउन्सिल ऑफ़ इंडिया द्वारा संचालित आल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानि एआईबीई देना होगा, जिसके बाद ही आप वकालत के लिए योग्य घोषित कर दी जाएंगी। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन बार काउन्सिल ऑफ़ इंडिया में हो जायेगा और तब आप वकील के तौर पर काम करने की योग्यता प्राप्त कर लेंगीं।

एकेडमिक्स में जाएं

यदि आपका ध्येय केवल एक वकील की तरह भारत के किसी भी न्यायलय में वकालत को अपना करियर बनाना है, तो इसमें एलएलएम (लॉ में पोस्ट ग्रैजुएट) की कोई भूमिका नहीं है। इसके लिए आपकी एलएलबी की डिग्री ही पर्याप्त है। एलएलएम और पीएचडी मुख्य रूप से वे महिलाएं करती हैं, जो लॉ के क्षेत्र में एकाडेमिक्स में जाना चाहती हैं और आगे चलकर किसी लॉ कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में अपना करियर बनाना चाहती हैं। अगर आप किसी कानून विशेष में स्पेशलाइजेशन करना चाहती हैं, तो पीजी और पीजी डिप्लोमा स्तर पर स्पेशलाइजेशन के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं।

एनवायरमेंटल लॉयर

अगर आप प्रकृति के संरक्षण के बारे में गंभीरता से सोचती हैं तो एन्वायरमेंटल लॉयर बनने के बारे में सोच सकती हैं। इसके जरिए आप प्राकृतिक संपदा के नष्ट होने से जुड़ी चीजों को बचाने की बात कह सकती हैं। इसके तहत आप पब्लिक इंट्रस्ट लिटिगेशन भी डाल सकती हैं। इसके अलावा एन्वायरमेंटल लॉयर्स की जरूरत एनजीओज में भी होती है, जो प्रकृति को होने वाले नुकसान पर आवाज उठाते हैं।

साइबर लॉयर

टेक्निकल एडवांसमेंट के दौर में साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इन पर काबू पाने के लिए साइबर लॉयर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर फर्जी ई-मेल भेजना, सोशल अकाउंट हैक करना, कंपनियों के साथ फॉड, खातों से फर्जी तरीके से पैसे निकालना, एसएमएस हैकिंग, मोबाइल क्लोनिंग जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसे देखते हुए आप कंप्यूटर एंड डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के बारे में भी सोच सकती हैं।

पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉयर

कई बार लोग अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति की खोज को अपना नाम दे देते हैं, इससे सुरक्षा देता है पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉ। कानूनी तौर पर अगर कोई थर्ड पार्टी मूल प्रॉडक्ट को बनाना चाहती है, तो उसे इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होती है और उस पर रॉयल्टी शुल्क देना पड़ता है। बौद्धिक संपदा यानी Intellectual Property बिजनेस के उभरते हुए क्षेत्रों में से एक है और इसमें यंग प्रोफेशनल्स की अच्छी खासी मांग है।

लेबर लॉयर

कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकार लेबर लॉ के तहत आते हैं। अक्सर कंपनियों में काम कर रहे इंप्लॉई अपने अधिकार और अन्य विवादों को लेकर अदालत में पहुंच जाते हैं। लेबर लॉ से जुड़े मामलों में इजाफा होने की वजह से इसमें भी आपके लिए आपके लिए अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं।

इंटरनेशनल लॉयर

अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है और आपकी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में रुचि है तो आप इंटरनेशनल लॉयर बनने के बारे में भी सोच सकती हैं। इसके तहत विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों से जुड़ी समस्याओं का कानूनी तरीके से हल निकाला जाता है।

कॉरपोरेट लॉयर

देश में कंपनियों के बढ़ते प्रसार के बीच आजकल कॉरपोरेट लॉ का स्कोप भी काफी अच्छा है। इसके तहत कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स अपने यहां रखती हैं, जो उन्हें अपनी कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सलाह दे सकें। कॉरपोरेट लॉयर्स के तौर पर अच्छा तजुर्बा हासिल होने पर अच्छा पे-पैकेज भी मिलता है।

ये हैं जरूरी गुण

- बेहतर संवाद क्षमता
- अच्छी मेमोरी
- हाजिरजवाब
- तार्किक और चीजों का विश्लेषण करने में निपुण
- धैर्यवान होने का गुण
- समस्याओं के अनूठे हल निकालने में सक्षम
- कानूनी पहलुओं की अच्छी जानकारी
- समर्पण और कड़ी मेहनत

यदि आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से सामने वाले के सामने रख सकते हैं और जिसे भारत के कानून के बारे में नई-नई बात जानने की उत्सुकता बनी रहती है, आपके मन में अक्सर किसी व्यवस्था को लेकर उदगार पैदा होते हैं और आप समझते हैं कि यदि आपके हाथ में कानून होता तो इसे ठीक करने की कोशिश करते , तो फिर लॉ का क्षेत्र आपके लिए ही है। अगर आप लॉ के बाद इसमें करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इसमें काफी अच्छी संभावनाएं हैं।

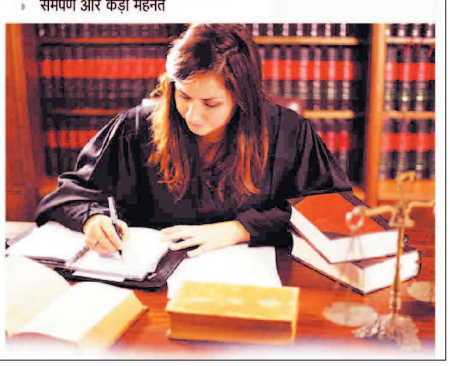

17 को कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव - दीपक बैज, मनरेगा बचाओ संग्राम तथा स्थानीय मुद्दो पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कांग्रेस 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम तथा प्रदेश के स्थानीय मुद्दो बिजली के दाम में बढ़ोत्तरी, किसानो से धोखा, धान खरीदी पर वादा खिलाफी, गैस सिलेंडर के दामो की बढोत्तरी जैसे मुद्दो को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट सहित राज्य के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सहित आम आदमी बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा घेराव के लिए जिलोंवार तथा विधानसभा प्रभारियों की नियुक्तियां की जा चुकी है। प्रदेश के कोने-कोने से कांग्रेसजन विधानसभा घेराव में शामिल होकर डबल इंजन की सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। घेराव की तैयारी के लिये प्रदेश मुख्यालय में दो बैठकें हो चुकी है तथा जिलेवार बैठको का भी सिलसिला चल रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कानन से महात्मा गांधी का नाम हटाकर तथा मनरेगा को कानून से बदल कर योजना बनाकर केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त करने की साजिश रचा है। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की सरकार बनने के बाद मनरेगा में काम तो लगभग बंद किया जा चुका है। मनरेगा बंद होने के कारण प्रदेश के मजदूर पलयान कर दूसरे प्रदेश चले गये है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मनरेगा के नये स्वरूप वीबी जी राम जी में मोदी सरकार ने केंद्रांश को घटाकर केंद्रांश और राज्यांश का औसत 60-40 कर दिया है। पहले यह योजना 100 प्रतिशत केंद्र पोषित योजना थी। जब केंद्र सरकार 100 प्रतिशत राशि देती थी तब तो राज्य सरकारें इस योजना को लागू करने में कोताही बरतती थी, अब जब राज्य को 40 प्रतिशत राशि वहन करना होगा तब तो राज्य सरकारें इसको लागू करने में और कोताही बरतेंगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी (मनरेगा) के रूप में रोजगार को कानूनी गारंटी दिया था लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा की साय सरकार का नाम बदलकर बंद करने की साजिश कर रही है। मोदी सरकार मनरेगा को बंद करना चाहती है। मोदी सरकार के 11 सालों में मनरेगा को पर्याप्त बजट नहीं दिया। हर साल मनरेगा के बजट में 30 से 35 प्रतिशत की कटौती की गयी है। पिछले 11 वर्षो में मनरेगा की मजदूरी में न्यूनतम वृद्धि है, जिसके कारण मजदूर वर्ग की आय स्थिर हो गयी है तथा महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है।

खास खबर

प्रदेश में गैस की संकट उपभोक्ता परेशान हो रहे है - कांग्रेस

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

गैस सिलेंडर की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर सरकार का दावा झूठा

रायपुर। घरेलू गैस की आपूर्ति पिछले एक हफ्ते से बाधित है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि घरेलू गैस नहीं मिल रहा तथा कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अचानक से रोक दिया गया है। पूरे प्रदेश में गैस के लिए हाहाकार मचा है, बिलासपुर में तो गैस एजेंसियों के सामने लाइन लगी हुई है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री और सरकार यह झूठा दावा कर रही है कि कोई कमी नहीं है, पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार ने घरेलू गैस के दाम 60 और कमर्शियल गैस के दाम 115 बढ़ा दिया और सरकार उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति भी नहीं कर पा रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि गैस बुकिंग नंबर को जानबूझकर बिजी कर दिया गया है, सर्वर डाउन कर दिया गया है, सिलेंडर की बुकिंग नहीं लग रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की अगली बुकिंग के लिए 4 दिनों का अंतराल बढ़ाना, 21 दिन के बजाय अब 25 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर के बुकिंग की बाध्यता इस बात का प्रमाण है कि उपलब्धता और सप्लाई में अड़चन तो है, लेकिन यह सरकार वास्तविक परिस्थिति से इंकार कर रही।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि अचानक से कमर्शियल गैस की सप्लाई अघोषित तौर पर रोक देने से घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग होगा, कालाबाजारी होगी और होटल व्यवसाईयों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे कुक्ड फूड के दाम भी प्रभावित होंगे। राजधानी के लगभग आधे रेस्टोरेंट गैस की किल्लत के कारण बंद होने की स्थिति में है। महंगाई, मोदी सरकार के 12 साल के दौरान जब-जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड मिल के दामों में कमी आई है उसका लाभ लगातार जनता से छिन गया और अब कीमतें बढ़ाकर महंगाई के बोझ से जनता का पसीना निकल जा रहा है।

विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का किया शुभारंभ

कोरोना में आर्थिक रूप से कमजोर हुए बिजली उपभोक्ताओं को मजबूत करेगी एमबीबीएस योजना,प्रदेशभर के सभी बिजली वितरण केंद्रों व कार्यालयों में पंजीयन हुआ शुरू

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की लांचिंग की। इसमें कोरोना महामारी व अन्य कारणों से बकाया विद्युत बिलों के भुगतान से उपभोक्ताओं को सीधे राहत प्रदान की जाएगी। प्रदेश 29 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 758 करोड़ रुपए तक की सीधे छूट मिलेगी। इतनी बड़ी राशि पहली बार एकमुश्त बिजली उपभोक्ताओं की माफ की जाएगी।

राजधानी रायपुर के मेडिकल कालेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने एवं प्रोटोकाल के कारण कई महीने तक मीटर रीडिंग नहीं हो पाई थी। जब लोगों को एकसाथ कई महीने का बिल मिला तो वे इसे जमा नहीं कर पाए। कोरोना महामारी के कारण अनेक लोग आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो गए थे कि इन्हें जमा करने में अक्षम हो गए। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजनाझ2026 प्रारंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत बिलों के भुगतान में राहत प्रदान की जाएगी तथा उपभोक्ताओं को सरल और सुविधाजनक तरीके से अपने बकाया बिलों का निराकरण करने का अवसर मिलेगा।

यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। भुगतान के बाद उन्हें एम-ऊर्जा (मुख्यमंत्री उर्जा राहत जन अभियान) का लाभ मिलना शुरु हो जाएगा, इसके तहत उन्हें 400 यूनिट तक खपत करने पर 200 यूनिट तक आधा बिल राशि की छूट मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने एमबीबीएस योजना के तहत लाभान्वित उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2931 हितग्राहियों को राज्य शासन की ओर से देय सब्सिडी 8 करोड़ 79 लाख रूपए का बटन दबाकर हस्तानांतरण किया गया। इसके अलावा पीएम कुसुम सहित अन्य योजना के हितग्राहियों को भी प्रमाण पत्र दिया गया। महिला स्वसहायता समूह को पीएम सूर्यघर का वेंडर बनाने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

ऊर्जा सचिव तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन एवं जनरेशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इस योजना का नाम एमबीबीएस (मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान) योजना रखा जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2023 की स्थिति में बकाया राशि को आधार मानकर उपभोक्ताओं को मूल राशि एवं अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान की जाएगी। यह पहली योजना है, जिसमें 758 करोड़ रुपए सीधे-सीधे माफ किये जाएंगे। बिजली के क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि की छूट पहली बार दी जा रही है। इसके लिए योजना में शामिल उपभोक्ताओं को पंजीयन की सुविधा मोर बिजली एप, विद्युत वितरण केंद्रों में 30 जून तक पंजीयन कराना होगा। भुगतान करते समय उपभोक्ता सावधानी बरतें, केवल किसी तरह का शंका होने पर वितरण केंद्र के अधिकारियों से संपर्क करें।

रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि एमबीबीएस योजना को इस तरह याद रखें, मोर बेटा बिष्णुदेव साय। इस योजना से गरीब, किसानों के साथ आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह अच्छी योजना है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीमसिंह कंवर ने कहा कि इस योजना का क्रियान्वयन आज से ही सभी वितरण केंद्रों में कर दिया गया है। इसके लिए गांव-गांव में शिविर लगाये जाएंगे, ताकि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिले।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल, संदीप यदु, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव सूर्यप्रकाश शुक्ला, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के निदेशक आरए पाठक सहित कार्यपालक निदेशक व मुख्य अभियंता गण उपस्थित थे।

चैत्र नवरात्रि व भगवान झूलेलाल जयंती का होगा भव्य आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

श्री माँ दुर्गा झूलेलाल विकास समिति एवं झूलेलाल धाम मंदिर कालीबाड़ी, मिलाई के तत्वावधान में हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 के पावन अवसर पर चैत्र नवरात्रि एवं भगवान झूलेलाल जयंती का भव्य एवं धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों का शुभारंभ चैत्र नवरात्रि प्रथम दिवस 19 मार्च 2026, गुरुवार से होगा तथा भगवान झूलेलाल जयंती 20 मार्च को श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई जाएगी।

चैत्र नवरात्रि पर्व 19 मार्च के दिन घट स्थापना एवं मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। माँ दुर्गा सप्तशती पाठ, भजन-कीर्तन, श्रृंगार, महाआरती एवं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं से निवेदन किया गया है कि वे अपनी मनोकामना ज्योति स्वयं उपस्थित होकर प्रज्वलित करें एवं धर्म लाभ प्राप्त करें। भगवान झूलेलाल जयंती के अवसर पर सुबह 7 बजे सार्वजनिक मंच से जुम्बा डांस, मेराथन दौड़, सुबह 10 बजे स्कूटर एवं बाइक रैली, संध्या में शोभायात्रा, बहाराणा साहिब पूजा एवं पल्लव आरती आयोजित की जाएगी। रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक झूलेलाल धाम परिसर में विशाल भंडारा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रहेगा।

आयोजन समिति द्वारा समाज एवं नगरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सफल बनाने की अपील की गई है। श्रीराम सिंधी पंचायत के अध्यक्ष दिलीप पवानी सहित भीमसेन सेतपाल, प्रतापराय शिवानी, धमर्दास बत्रा, मनोहर थदानी, प्रकाश डिंगा, मनोहर शिवानी, गोपी राजपालानी, अशोक गंगवानी, राम छुगनी, प्रकाश मदनानी, मुकेश गणेशानी एवं अनिल पोपटानी मंदिर समिति प्रभारी अर्जुन सचदेव (मो. 9302158000) एवं अशोक चेतवानी मो. 9827116975 से संपर्क कर सकतें हैं। यह जानकारी श्रीराम सिंधी पंचायत, वैशाली नगर के मीडिया प्रभारी मनोहर कृष्णानी द्वारा प्रदान की गई।

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने पीएमश्री विद्यालय कोपेडीह का किया आकस्मिक निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम कोपेडीह स्थित पीएमश्री विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेटक्टर ने कक्षा में विद्यार्थियों के साथ बैठकर पढ़ाई से संबंधित चर्चा की तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी ली। बच्चों ने विश्वास पूर्ण अंग्रेजी में जवाब दिया।

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने जिले में बेहतर शैक्षणिक परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित सम्पर्क लर्निंग प्रोग्राम का कक्षा में जाकर अवलोकन किया। उन्होंने शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से चर्चा कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जानकारी ली तथा इसे प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने तथा नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल उपस्थित थे।

85% से अधिक चालानी कार्रवाई, 31% कम सड़क दुर्घटना मृत्यु - यातायात पुलिस दुर्ग की सख्ती का सकारात्मक प्रभाव

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा वर्ष 2026 में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार सघन वाहन जांच एवं चालानी कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले, शराब पीकर वाहन चलाने वाले (Drink & Drive) तथा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध नियमित अभियान संचालित किया जा रहा है।

यातायात पुलिस द्वारा की गई सख्त एवं निरंतर कार्रवाई का सकारात्मक प्रभाव सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। वर्ष 2025 में जनवरी से 10 मार्च तक सड़क दुर्घटनाओं में कुल 89 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई थी (जनवरी-47, फरवरी-30, मार्च 10 मार्च तक-12), जबकि वर्ष 2026 में इसी अवधि में यह संख्या घटकर 62 हो गई है (जनवरी-36, फरवरी-23, मार्च 10 मार्च तक-03)। इस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

इसी अवधि में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा चालानी कार्रवाई में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्ष 2025 में जनवरी से 10 मार्च तक कुल 14,162 चालान किए गए थे (जनवरी-5364, फरवरी-7245, मार्च 10 मार्च तक-1553), जबकि वर्ष 2026 में इसी अवधि में कुल 26,234 चालान किए गए हैं (जनवरी-8662, फरवरी-14704, मार्च 10 मार्च तक-2868)। इससे स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा नियमों के पालन हेतु सख्ती से कार्रवाई बढ़ाई गई है।

यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा विशेष रूप से दुर्ग-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, सेंट्रल एवेन्यू मार्ग, दुर्ग शहर, सुपेला चौक, नेहरू नगर चौक, पावर हाउस चौक एवं अन्य दुर्घटना संभावित स्थानों पर लगातार वाहन जांच, हेलमेट चेकिंग तथा ड्रिंक एंड ड्राइव जांच की जा रही है। साथ ही नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु समझाइश भी दी जा रही है।

यातायात पुलिस दुर्ग आम नागरिकों से अपील करती है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं तथा सभी यातायात नियमों का पालन करें। सुरक्षित एवं जिम्मेदार वाहन संचालन से ही सड़क दुर्घटनाओं में और अधिक कमी लाई जा सकती है।

मुस्कान संवाद संगोष्ठी : जहाँ परिवार, विश्वास और भविष्य को मिलता है नया सहारा

मुस्कान आत्मा का वह श्रृंगार है जो जीवन को भीतर से सुंदर बना देता है : आचार्य डॉ. अजय आर्य

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

ईश्वर को शास्त्रों में सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है- अर्थात सत्य, चेतना और आनंद का साकार रूप। इसी भाव को केंद्र में रखकर आयोजित मुस्कान संवाद संगोष्ठी में आचार्य डॉ. अजय आर्य ने कहा कि जब ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है, तो उसके भक्तों के चेहरे पर उदासी और तनाव क्यों दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार लोग भक्ति तो करते हैं, पर उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होती, जबकि सच्ची भक्ति का पहला लक्षण ही है- आनंदित और संतुलित जीवन।

सत्संग को संबोधित करते हुए उन्होंने हल्के हास्य के साथ कहा कि आजकल फोटो खिंचवाते समय फोटोग्राफर सबसे पहले यही कहता है—थोड़ा मुस्कुराइए। क्योंकि मुस्कान से तस्वीर सुंदर बनती है। फिर जब जीवन की तस्वीर हर क्षण ईश्वर के सामने बन रही है, तो वह मुस्कान से क्यों न सजे। उन्होंने कहा कि मुस्कान केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास की सबसे सरल अभिव्यक्ति है।

आचार्य डॉ. अजय आर्य ने कहा कि आज तनाव और अवसाद बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि मनुष्य भविष्य की चिंता में वतर्मान को नष्ट कर देता है। इस संदर्भ में उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक व्यक्ति संत के पास जाकर बोला-महाराज, मुझे बहुत चिंता रहती है, क्या करूँ? संत ने मुस्कुराकर कहा-चिंता हमें दे दो, और बदले में मुस्कान ले जाओ। वह व्यक्ति बोल-महाराज, चिंता देना आसान नहीं। संत ने उत्तर दिया-यही तो समस्या है, लोग चिंता को पकड़कर रखते हैं और खुशी को छोड़ देते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि झुरियाँ उम्र से नहीं, चिंता से आती हैं और मुस्कान आत्मा का वह श्रृंगार है जो जीवन को भीतर से सुंदर बना देता है।

प्रवचन के दौरान उन्होंने धर्म के वास्तविक स्वरूप पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि धर्म केवल मंदिर, घंटी, पूजा या कमर्कांड तक सीमित नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है—व्यक्तित्व का विकास और परोपकार की भावना। इसी संदर्भ में उन्होंने नीतिशतकम का प्रसिद्ध विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि संसार में चार प्रकार के मनुष्य होते हैं-पहले वे सत्पुरुष, जो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। दूसरे सामान्य जन, जो स्वार्थ और परार्थ में संतुलन रखते हैं। तीसरे वे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुँचाते हैं। और चौथी श्रेणी वे लोग हैं जो अपना लाभ हो या न हो, दूसरों को नुकसान पहुँचाने में ही आनंद अनुभव करते हैं।

उन्होंने कहा कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को पहली श्रेणी में लाकर सत्पुरुष बनाना है। अपने प्रवचन के निष्कर्ष में आचार्य डॉ. अजय आर्य ने अत्यंत सार्थक और मार्मिक बात कही-ईश्वर यह नहीं पूछेगा कि आपने कितनी माला जपी, कितने कमर्कांड किए या कितनी बार मंदिर गए। वह यह देखेगा कि आपके कारण कितने चेहरे मुस्कुराए और कितनों का जीवन थोड़ा हल्का हुआ। उन्होंने एक चुटीला प्रसंग सुनाते हुए कहा कि एक व्यक्ति रोज मंदिर जाकर लंबी प्राथर्ना करता था, पर घर लौटकर सब पर गुस्सा करता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा-पिताजी, आप मंदिर में भगवान से क्या माँगते हैं? उसने कहा-शांति। बेटे ने मासूमियत से उत्तर दिया—तो थोड़ा घर पर भी ले आया कीजिए। इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि धर्म का असली प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए।

आचार्य डॉ. अजय आर्य ने विशेष रूप से वतर्मान पीढ़ी की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज के बच्चे और युवा अपने करियर, प्रतिस्पर्धा, भविष्य की अनिश्चितता और सामाजिक दबाव के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में उन्हें डांटने वाले नहीं, बल्कि ऐसे सच्चे मार्गदशर्कों की आवश्यकता है जो बिना टोका-टाकी के सही दिशा दिखाएँ, उनका आत्मविश्वास बनाए रखें और उनके भीतर की क्षमता को पहचानने में सहायता करें।

इसी उद्देश्य को लेकर आचार्य डॉ. अजय आर्य के नेतृत्व में मुस्कान संवाद संगोष्ठी जैसी पहल की जा रही है। यह एक ऐसी सामाजिक और आध्यात्मिक पहल है जिसमें बिना किसी शुल्क, बिना धार्मिक प्रपंच और बिना औपचारिकताओं के परिवारों को एक साथ बैठाकर संवाद की संस्कृति को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इन बैठकों में घर-परिवार, माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद स्थापित कर उनकी मनोवैज्ञानिक, वैचारिक और भावनात्मक समस्याओं को समझने और सुलझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि परिवारों में सामंजस्य बना रहे और बच्चों का व्यक्तित्व आत्मविश्वास के साथ विकसित हो सके। वतर्मान में रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, राजनांदगांव के साथ-साथ दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में भी इस प्रकार की संवाद बैठकों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस सेवा कार्य में अध्यात्म पथ संस्था, वैदिक सत्संग समिति, पतंजलि तथा विभिन्न गुरुकुलों से जुड़े अनेक विद्वान और समाजसेवी निस्वार्थ भाव से सहयोग कर रहे हैं।

कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका मधु त्रेहन रहीं। इस अवसर पर शिव अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल (अध्यक्ष वैदिक सत्संग समिति), पुरुषोत्तम अग्रवाल, राव साहब, अशोक त्रेहन, मधु त्रेहन, राव जयश्री, शशि जायसवाल और सिद्धार्थ की सक्रिय एवं गरिमामयी उपस्थिति रही। क्या है मुस्कान संवाद संगोष्ठी? यह पाँच से दस परिवारों या मित्रों के बीच होने वाला एक सहज और आत्मीय संवाद मंच है, जहाँ जीवन, परिवार, बच्चों के भविष्य और अध्यात्म से जुड़े प्रश्नों पर खुलकर चर्चा की जाती है। इसमें किसी प्रकार का खर्च, कमर्कांड या औपचारिकता नहीं होती। केवल संवाद, आत्मीयता और जीवन को बेहतर बनाने वाले विचारों का आदान-प्रदान होता है।

जिन घरों में बच्चे तनाव में हैं, आत्मविश्वास खो रहे हैं या जहाँ परिवार को प्रेरणा और संवाद की आवश्यकता है, वहाँ ऐसे आयोजनों के माध्यम से निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। आचार्य डॉ. अजय आर्य का मानना है कि आज की पीढ़ी अत्यधिक मानसिक दबाव झेल रही है। ऐसे समय में हमें सकारात्मक और सहज भाव से उनके पास पहुँचना होगा। यही सच्चा सत्संग है और यही मुस्कुराते हुए जीवन जीने की कला भी।

विद्युत विभाग के मरम्मत कार्य के चलते आज कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति होंगे प्रभावित

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा अंतर्गत बोरसी, पोटिया, पुलगांव, बघेरा, सिकोला बस्ती, कातुलबोर्ड तथा गंजपारा सहित आसपास के क्षेत्रों में 42 एमएलडी इंटेकवेल के माध्यम से फिल्टर प्लांट के जरिए पेयजल आपूर्ति की जाती है और 24 एमएलडी क्षेत्र में आने वाले पदमनाभपुर टंकी- वार्ड नं. 43 (कसारीडीह, पूर्व), वार्ड नं. 44 (बाबा गुरूघासीदास वार्ड), वार्ड नं. 45 (पद्मनाभपुर पश्चिम), वार्ड नं. 46 (पद्मनाभपुर पूर्व), शंकर नगर टंकी - वार्ड नं. 10 (शंकर नगर, पश्चिम), वार्ड नं. 11 (शंकर नगर, पूर्व), वार्ड नं. 12 (मोहन नगर, पश्चिम), वार्ड नं. 13 (मोहन नगर, पूर्व), शक्तिनगर टंकी - वार्ड नं. 17 (औद्योगिक नगर, उत्तर), वार्ड नं. 18 (औद्योगिक नगर, दक्षिण), वार्ड नं 19 (शहीद भगत सिंह दक्षिण), वार्ड नं. 20 (शहीद भगत सिंह उत्तर), वार्ड नं. 21 (तितुरडीह), वार्ड नं. 22 (स्टेशन पारा), गिरधारी नगर टंकी वार्ड नं. 09 (स्वामी विवेकानंद वार्ड), वार्ड नं. 05 (मरारपारा), हनुमान नगर टंकी - वार्ड नं 19 (शहीद भगत सिंह दक्षिण), वार्ड नं. 20 (शहीद भगत सिंह उत्तर), वार्ड नं. 21 (तितुरडीह), ट्रांसपोर्ट नगर टंकी - वार्ड नं. 16 (करहीडीह), शनिचारी बाजार टंकी- वार्ड नं. 30 (तमेरपारा), वार्ड नं. 31 (आपापुरा), वार्ड नं. 32, वार्ड नं. 33 (चंडीमंदिर), वार्ड नं. 34 (शिव पारा), वार्ड नं. 35 (रामदेव मंदिर), वार्ड नं. 36 (गंजपारा), वार्ड नं. 37 (आजाद वार्ड), वार्ड नं. 38 (आंशिक) प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग द्वारा 24 एवं 42 एमएलडी शिवनाथ नदी इंटेकवेल में तकनीकी सुधार एवं आवश्यक मरम्मत कार्य किए जाने के कारण दिनांक 13 मार्च को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

विद्युत विभाग द्वारा आपूर्ति बंद रहने के कारण इंटेकवेल से संचालित पंपों का संचालन प्रभावित रहेगा, जिसके चलते संबंधित क्षेत्रों में द्वितीय पहर की जलापूर्ति में विलंब होने की संभावना है। नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि उक्त अवधि को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार पहले से ही पानी का संग्रह कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। तकनीकी कार्य पूर्ण होते ही जलापूर्ति को सामान्य रूप से पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा।

सेक्टर-6 सोसाइटी के सदस्य कर्मियों का हुआ समूह दुर्घटना, बीमा, हादसे में मौत पर नॉमिनी को मिलेंगे दस लाख

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित सहकारी संस्था इस्पात कमर्चारी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड सेक्टर-6 में एक संक्षिप्त आयोजन में सोसाइटी की ओर से भिलाई स्टील प्लांट में सेवारत अपने सदस्य कर्मियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (जीपीएआईएस) आने वाले वर्ष के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करवाते हुए औपचारिकताएं पूरी की गई।

इस पॉलिसी से दुर्घटना जनित निधन पर दस लाख की राशि सदस्य के नॉमिनी को देय होगी। आयोजन में अध्यक्ष बृज बिहारी मिश्र व सदस्यों की ओर से बीमा की प्रीमियम राशि 1932917 (उन्नीस लाख बत्तीस हजार नौ सौ सत्रह) का चेक आईसीआईसीआई कंपनी के प्रतिनिधि गौरव सोलंकी(वरिष्ठ प्रबंधक),शादाब खान (विक्रय प्रबंधक) एवं रवेंद्र द्विवेदी (क्षेत्रीय प्रबंधक पालिसी बाजार)को दिया गया।

अध्यक्ष बृज बिहारी मिश्र ने इस दौरान बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस साल प्रीमियम में 241 सदस्य की कमी आई है। गत वर्ष सदस्यों से उपरोक्त (10 लाख) बीमित राशि के लिए 750 का प्रीमियम दिया गया था,जबकि इस वर्ष उपरोक्त राशि के लिए मात्र 509/व्यक्ति का प्रीमियम दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में बीमा क्षतिपूर्ति राशि दस लाख रुपए होगी। दुर्घटना के फलस्वरूप घायल/अनफिट होने पर क्षतिपूर्ति राशि 5हजार/साप्ताहिक होगी।

अध्यक्ष मिश्र ने बताया कि समूह सदस्यों के इंश्योरेंस क्लेम (बीमा दावा)बीएसपी ओपीडी बुक में उल्लेखित ट्रीटमेंट या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उल्लेखित ट्रीटमेंट के आधार पर देय होगा। सदस्यों को दुर्घटना की सूचना सोसायटी के माध्यम से लिखित में देनी आवश्यक होगी। इस आयोजन में उपाध्यक्ष अमिताब वर्मा, संचालक मंडल सदस्य कुलेश्वर चंद्राकर और सोसाइटी के प्रबंधक एम मुरलीधर प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

8 करोड़ की अवैध अफीम खेती का भंडाफोड़, राजस्थान से चौथा आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पुलगांव थाना क्षेत्र में करीब 5 एकड़ 62 डिसमिल जमीन पर उगाई जा रही अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में बीज सप्लाई करने वाले चौथे आरोपी को भी राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त किए गए अफीम के पौधों की अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम समोदा, झेनझरी और सिरसा के बीच स्थित खेत में उगाई जा रही अफीम की फसल को जब्त किया था। इस मामले में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। जांच के दौरान सामने आया कि इस अवैध खेती के लिए बीज उपलब्ध कराने में एक अन्य आरोपी की अहम भूमिका थी, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए चौथे आरोपी की पहचान छोटू राम (62 वर्ष) निवासी जोधपुर, राजस्थान के रूप में हुई है। आरोपी लंबे समय से फरार था। पुलिस टीम उसकी तलाश में राजस्थान पहुंची और वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अफीम की खेती के लिए बीज सप्लाई करने में छोटू राम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पहले तीन आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार इस मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें विकास बिश्नोई (जोधपुर, राजस्थान) विनायक ताम्रकार (तेमरापारा, दुर्ग) मनीष उर्फ गोलू ठाकुर (समोदा) शामिल हैं। जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क मिलकर अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहा था। खेती में इस्तेमाल किए गए उपकरण भी जब्त पुलिस ने आरोपियों से खेती में इस्तेमाल किए जा रहे कई मशीनरी और वाहन भी जब्त किए हैं। इनमें 2 ट्रैक्टर 2 जेसीबी 2 मोटरसाइकिल 1 हार्वेस्टर शामिल हैं। इन सभी उपकरणों की अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपी छोटू राम के पास से 2220 रुपये नकद और एक स्मार्टफोन भी बरामद किया गया है।

यह पूरी कार्रवाई एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई। इस ऑपरेशन में एसीसीयू दुर्ग, थाना पुलगांव और चौकी जेवरा-सिरसा की संयुक्त पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है और इस अवैध नशा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एनकाउंटर में ढेर अमित जोश के जीजा ने की युवती के साथ अश्लील हरकत, गिरफ्तार

दुर्ग। जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एनकाउंटर में ढेर किए गए अपराधी अमित जोश के जीजा लक्की जॉर्ज उर्फ सोनू ने एक युवती को मीटिंग के बहाने लॉज में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और इलाके में जुलूस निकालकर कानून का संदेश दिया।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता पिछले कुछ समय से अकाउंट से जुड़ा कार्य कर रही थी। लक्की जॉर्ज, जो अमित जोश का जीजा है और खुद भी कई अपराधिक मामलों में नामजद रहा है, व्यापार से जुड़ी बातें करने के बहाने पीड़िता से साप्ताहिक मीटिंग करता था। 5 मार्च को आरोपी ने उसे पावर हाउस इलाके के एक लॉज में मीटिंग के लिए बुलाया। पीड़िता ने बताया कि शाम करीब 4 बजे वह लॉज पहुंची। वहां कमरे में आरोपी अकेले बैठा शराब पी रहा था। जैसे ही पीड़िता कमरे से बाहर जाने लगी, आरोपी ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। पीड़िता ने किसी तरह धक्का देकर बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को यह घटना बताई, तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी लक्की जॉर्ज के खिलाफ धारा 74 बीएनएस और 351(3) आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को घटना स्थल के पास जुलूस निकालकर दिखाया, जिससे समाज में कानून का संदेश गया।

अवैध अफीम खेती मामले में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन

प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर भाजपा कार्यालय घेराव, पुलिस से हुई झूमाझटकी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड, भाजपा सरकार पर लगाए संरक्षण के आरोप

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-भिलाई

जिले के जेवरा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम समोदा में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार द्वारा अपने फार्म हाउस में बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध अफीम की खेती के मामले को लेकर दुर्ग में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी आक्रामक तेवर में नजर आई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जिला भाजपा कार्यालयों का एक साथ घेराव किया गया, जिसके तहत दुर्ग में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर एवं दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के संयुक्त नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन, दुर्ग से भाजपा कार्यालय घेराव के लिए रैली के रूप में निकले। इस दौरान कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े।

भारी पुलिस बल तैनात, कई लेयर में की गई बैरिकेडिंग

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन द्वारा पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। भाजपा कार्यालय जाने वाले मार्ग पर कई लेयर में बैरिकेडिंग कर रास्ते को रोक दिया गया था, ताकि कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय तक न पहुंच सकें।

भाजपा सरकार पर संरक्षण का आरोप

प्रमुख रूप से उपस्थित पूर्व केबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के फार्म हाउस में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी, जो कानून के खिलाफ गंभीर अपराध है। इसके बावजूद भाजपा सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपने नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही है।

जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और भाजपा नेता ही खुलेआम अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्री ठाकुर ने सरकार से सवाल किया की अफीम की इस अवैध खेती में कौन-कौन से मंत्री और अधिकारी शामिल हैं?

नव्या मलिक का नाम सरकार की सूची से किसके दबाव में बाहर किया गया?, नव्या मलिक कितनी बार विदेश गई और किन लोगों के साथ विदेश यात्रा की?, भाजपा नेता विनायक ताम्रकार मुख्यमंत्री निवास में कब-कब आया है?, विनायक ताम्रकार के किन-किन नेताओं से संबंध हैं?, क्या भाजपा सरकार विनायक ताम्रकार द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को हटाकर उस पर कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएगी?

दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेगी और जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक कांग्रेस का जन आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। श्री बाकलीवाल ने आगे कहा की मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार को न बनाकर सरकार उन्हें बचाने में लगी हुई है।

पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुवे कहा समोदा में कई जारी भाजपा नेता द्वारा अवैध अफीम खेती सरकार में बैठे मंत्रियों के संरक्षण के बिना संभव नही है। वोरा ने गृहमंत्री विजय शर्मा पर सीधा आरोप लगाते हुवे उनके द्वारा अफीम माफिया भाजपा नेता को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

इस दौरान पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, पूर्व महापौर आर एन वर्मा, दीपक दुबे, राजेंद्र साहू, कोषाध्यक्ष विक्रांत अग्रवाल, उपाध्यक्ष शमशीर कुरेशी, विशाल देशमुख, रिवेन्द यादव, राजीव गुप्ता, जयश्री वर्मा, रूपेश देशमुख, योगिता चंद्राकर, देवेंद्र देशमुख, जामयुन गजपाल, प्रकाश ठाकुर, प्रवक्ता नासिर खोखर, राम सुर्य वंशी, आनंद कपूर ताम्रकार, गुरदीप सिंह भाटिया, मनीष बघेल, अल्ताफ अहमद, श्रीमती देवश्री साहू, संजय बत्रा, सुमित घोष, विनोद सेन, सुशील भारद्वाज, शिशिर कांत कसर, मीणा पाल, राकेश साहू ,राजा विक्रम बघेल, निखिल खिचड़िया, पालेशवर ठाकुर, धर्मेंद्र साहू, सुमित नांरग, लोचन यादव, रोहित यादव, अभिशेक जांगडे, श्यामा चरण मनहर, शिवकुमार वर्मा, देवेन्द्र देशमुख, उमेश साहू, संतोष बाफना, कांत वर्मा, रजत नायक, मोहित वाल्दे, जय साहू, उषा सोनी, उमेश बंजारे, धरम बर्रे, कमलेश वर्मा, हीरा वर्मा, जगदीश मार्कण्डेय, आशीष अग्रवाल, पंकज शिकर, विक्की, कमलेश वर्मा, हेमंत, जसवंत गायकवाड़, योगेश गायकवाड़, मनोज वर्मा, जितेन्द्र वर्मा, देवेन्द्र गायकवाड़, दिलीप बंजारे, भोला निषाद, युवराज निर्मलकर, जितु टंडन, नागमणी, जमुनादेवी, भारती साहू, सतीजोशी, कमलेश साहू, मन्नू यादव, ओमकार निर्मल, गजू साहू, सुनीता चेनेवार, सरोजनी चंद्राकर, पुष्पा यादव, हेमलता साहू, दीप्ति देवांगन, राजकुमार वर्मा, अभिनव बघेल, रंजन बाई, महेश्वरी ठाकुर, शकून ढिमर, नंदा राऊत, लछ्मी साहू, देवश्री साहू, बंटी धनकर, शिवकुमार साहू, विष्णू प्रसाद, हेमंत साहू, अजीत यादव, परमिला साहू ,दुरपति साहू, प्रकाश सिंह ठाकुर, ज्वाला प्रसाद साहू, संतलाल बंजारे, राजेश मानिकपुरी, हिम्मत लाल ढिमर, अगनू पाल, द्वारिका साहू, ,खुर्शीद अहमद, भीम चौहान, रायसेन ढिकोला, राकेश यादव ,संजय धनकर ,अनूप वर्मा ,आयुष शर्मा, गौरव उमर, चिराग शर्मा, विनोद साहू, जमुना साहू, विजयंत पटेल, नंदकिशोर शर्मा, अविनाश यादव, तिलक सिंह राजपूत, गुलाब देवांगन, अब्दुल गनी, यस मानिकपुरी, प्रांशु सिंह, हरीश सिन्हा ,चंद्र मोहन, जगमोहन ढीमर, केडी देवांगन सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी, एक बैरिकेड टूटे

जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी देखने को मिली। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए दो बैरिकेड लेयर तोड़ दिए और मुख्य बैरिकेड तक पहुंचने का प्रयास किया। मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही और पुलिस अधिकारियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।

आवासीय कॉलोनी में राजनीति का शोर — और परेशान नागरिक

शहर की आवासीय कॉलोनियाँ इसलिए बसाई जाती हैं कि लोग अपने परिवार के साथ शांत और सुरक्षित वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें। परंतु जब वही कॉलोनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन जाए, तो सबसे अधिक परेशानी उन्हीं आम नागरिकों को झेलनी पड़ती है जो राजनीति से दूर रहकर केवल अपने रोजमर्रा के जीवन को सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं।

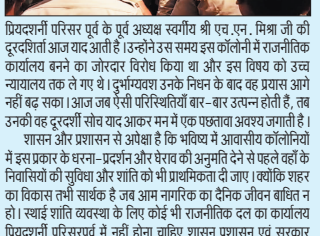

भिलाई के सुपेला क्षेत्र स्थित प्रियदर्शनी परिसर पूर्व में आज ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जब कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के घेराव की घोषणा के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस व्यवस्था और जगह-जगह बैरिकेड्स लगाए गए। प्रशासन की इस व्यवस्था का सीधा असर कॉलोनी के निवासियों पर पड़ा। सुबह का समय, जब बच्चे स्कूल और कॉलेज के लिए निकलते हैं, कमर्चारी अपने दफ्तरों के लिए जाते हैं, व्यापारी अपनी दुकानों के लिए निकलते हैं और मरीज अस्पतालों की ओर जाते हैं — उसी समय रास्तों के बंद होने से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

प्रियदर्शनी परिसर केवल एक कॉलोनी नहीं, बल्कि आसपास की बस्तियों और क्षेत्रों के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण मार्ग भी है। सुपेला बस्ती सहित कई इलाकों के लोग इसी मार्ग से अंडरब्रिज होते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। ऐसे में अचानक लगाए गए बैरिकेड्स ने आम नागरिकों की दिनचर्या को बाधित कर दिया। यह पहली बार नहीं है। कुछ समय पहले जब प्रदेश के मुख्यमंत्री का इसी राजनीतिक कार्यालय में आगमन हुआ था, तब भी कॉलोनी में इसी प्रकार की अव्यवस्था और असुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। रातों-रात रास्तों की व्यवस्था बदली गई, जिससे निवासियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

दरअसल मूल प्रश्न यह है कि क्या किसी घनी आबादी वाली आवासीय कॉलोनी के भीतर बड़े राजनीतिक दलों के कार्यालय होना उचित है? धरना, प्रदर्शन, नेताओं का आना-जाना और सुरक्षा व्यवस्था — यह सब मिलकर कॉलोनी की शांति और सामान्य जीवन को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में प्रियदर्शनी परिसर पूर्व के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री एच.एन. मिश्रा जी की दूरदर्शिता आज याद आती है। उन्होंने उस समय इस कॉलोनी में राजनीतिक कार्यालय बनने का जोरदार विरोध किया था और इस विषय को उच्च न्यायालय तक ले गए थे। दुर्भाग्यवश उनके निधन के बाद वह प्रयास आगे नहीं बढ़ सका। आज जब ऐसी परिस्थितियाँ बार-बार उत्पन्न होती हैं, तब उनकी वह दूरदर्शी सोच याद आकर मन में एक पछतावा अवश्य जगाती है।

शासन और प्रशासन से अपेक्षा है कि भविष्य में आवासीय कॉलोनियों में इस प्रकार के धरना-प्रदर्शन और घेराव की अनुमति देने से पहले वहाँ के निवासियों की सुविधा और शांति को भी प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि शहर का विकास तभी सार्थक है जब आम नागरिक का दैनिक जीवन बाधित न हो। स्थाई शांति व्यवस्था के लिए कोई भी राजनीतिक दल का कार्यालय प्रियदर्शनी परिसरपूर्व में नहीं होना चाहिए शासन प्रशासन एवं सरकार कॉलोनी की स्थाई शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीजेपी का कार्यालय यहां से हटाकर की कोई अन्य संस्था को दे दे जिससे कॉलोनी में स्थाई शांति व्यवस्था बनी रहे

अफीम की अवैध खेती : मुख्यमंत्री का कड़ा रुख, कलेक्टरों को सर्वे कर 15 दिवस में प्रमाण पत्र सहित रिपोर्ट देने के निर्देश

रायपुर। प्रदेश में अवैध रूप से अफीम की खेती का मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में संभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती न हो रही हो। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि 15 दिवस के भीतर प्रमाण पत्र सहित विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि राज्य में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन और कारोबार के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के पालन में आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को सर्वे कर जांच रिपोर्ट और उनके जिले में अफीम की खेती नहीं किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र जारी किया गया है।

रमजान के महीने में रोजा रख कर जुटे हैं इबादत में

नौकरी के साथ इबादत, माहे रमजान में चल रहे साथ-साथ

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

शहर के नौकरी पेशा लोग भी माहे रमजान में रोजा रख रहे हैं। इस दौरान अपने कामकाज के साथ-साथ इबादत भी खूब कर रहे हैं। खासकर सरकारी नौकरियों के साथ रोजेदार माहे रमजान की तमाम जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं।

ड्यूटी के साथ रोजा रखने में नहीं होती कोई परेशानी : असलम

शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चरोदा भिलाई 3 के बीईईटीओ सैय्यद असलम कहते हैं रोजा अल्लाह की बेहतरीन इबादत है इसको हर बालिग मर्द और औरत को रखना चाहिए हदीस का मफहूम है कि सभी इबादतों का दरवाजा रोजा है। ड्युटी करते हुए रोजा रखते कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होती है सहयोगी साथी भी कार्य में सहयोग करते हैं। सैय्यद असलम कहते हैं इस मुबारक महीने में अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, खानदान वालों के लिए, पड़ोसी, दोस्त अहबाब ,रिश्तेदारों और अपने मुल्क के लिए दुआ करें। खूब इबादत करें।

नहीं होती कोई परेशानी :मिराज

भिलाई इस्पात संयंत्र कोक ओवन बैटरी-11 सीडीसीपी में चाजमैंन मिराज अकरम कहते हैं कि रमजान का मुबारक महीना इबादतों का महीना है। प्यारे नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वस्सलम ने हमें जो तालीम दी है उसमें चलने पर कामयाबी है। अपने कार्यस्थल की गर्मी के बावजूद रोजा रखते हुए इस महीने की बरकत और रहमतों को पाने की कोशिश है। जनरल शिफ्ट रहती इसके बावजूद सभी कार्य करने में और रोजा रखकर तरावीह पढ़ने में कठिनाइयां नहीं होती है। यह महीना सब्र का है। हदीस में आता है जिसका सार है कि रोजा का बदला अल्लाह स्वयं देते हैं या स्वयं अपने को देते हैं।

बरकतों का महीना है रमजान :ऐमन

भिलाई इस्पात संयंत्र ऊर्जा प्रबंधन विभाग में सीनियर मैनेजर ऐमन अली कहते हैं कि माहे रमजान बड़ा बरकतो वाला महीना है। रोजा रखने से भूख प्यास की शिद्दत पता चलती हैं। गरीबी के चलते जिन्हें खाना मयस्सर नहीं होता, उनके प्रति सहानुभूति और करुणा जागृति होती है। रोजा संयम और धैर्य को पैदा कर जीवनशैली गुजारने की बेहतरीन अल्लाह की इबादत है। गरीब बेसहारा मिस्कीन यतीमों बेवा पर खर्च करने को प्रेरित करता है। जहां तक कार्यस्थल की बात है तो रोजे की हालत में भी अपने दायित्वों को बखूबी अंजाम देते हैं।

हिदायत का महीना है रमजान :नासिर

सुपेला संडे बाजार के कपड़ा व्यापारी नासिर कुरैशी कहते हैं कि रमजान महीने सभी लोगों के लिए खैरो बरकत और हिदायत लेकर आता है। रोजा रखने वाले को चाहिए कि उसके आदाब जो बताए गए हैं उनका अमल करें। रोजा रखकर हर बुराई से बचने की कोशिश करें और नेक काम ओर अल्लाह को राजी करने वाले कामों को करें और हुजूर की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाने की भरसक प्रयास कोशिश करें ताकि दुनिया में साफ सुथरा सादगी और अमन और खुशहाली पाकीजा माहौल बने।

ब्लास्ट फर्नेस के मुख्य महाप्रबंधक मनोज कुमार से भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा E D (works) के साथ संघ के महामंत्री चन्ना केशवलू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की बैठक में भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत कर्मचारियों को नॉन फाइनेंशियल अवार्ड प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था । भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के द्वारा भिलाई इस्पात मजदूर संघ की मांग को स्वीकार करते हुए नॉन फाइनेंशियल अवार्ड देने का निर्णय लिया। भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन इसका स्वागत करता है ।

इसी के तहत ब्लास्ट फर्नेस के मुख्य महाप्रबंधक मनोज कुमार से भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाक़ात कर सभी कर्मचारियों को पिछले साल की तरह इस वर्ष भी एमेजॉन गिफ़्ट बॉचर देने का प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव को मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा स्वीकृति प्रदान की । प्रतिनिधि मंडल में संघ के महामंत्री चन्ना केशवलू,संयुक्त महामंत्री प्रदीप कुमार पाल,अनिल राय, अरूप राय उपस्थित थे ।

पीआरजीआई सं.-CTHIN/25/A3746 यह हिंदी सांध्य दैनिक समाचार पत्र नई दृष्टिबिंद स्वामी एवं प्रकाशक आलोक तिवारी द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 से मुद्रित करवा कर। 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से प्रकाशित संपादक आलोक तिवारी मो. 7415469100 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारण न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।